पेज 02
एडीजी साब, सच जानना है तो दरबार लगाइए...

साप्ताहिक
# शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 03 अगस्त से 09 अगस्त 2026
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 08
कलेक्टर साहब; ये क्या हो रहा है...?

वर्ष : 02 अंक : 22 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 07 सुशासन की खेती में जहरीले थायरम पाउडर का छिड़काव

**पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के बाद नौकरशाहों की हरकतों से सांसद बृजमोहन भी आक्रोशित**

# फोन नहीं उठाना; धृष्टता या दुस्साहस..

नाराज सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सचिवालय से लेकर कार्मिक विभाग से शिकायत

बृजमोहन अग्रवाल का आरोप है कि IAS अमित कटारिया ने उनसे कहा – 'जो करना है कर लो!'

मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक हलकों में पसरा सन्नाटा, सीएम सचिवालय को है पता

प्रदेश में राजनेता बनाम नौकरशाह के टकराव का यह मामला अब खासी चर्चा में है

## वरिष्ठ आईएएस और स्वास्थ्य सचिव कटारिया पर सांसद बृजमोहन ने लगाया दुर्व्यवहार का आरोप

सुकांत राजपूत
मोबाईल नंबर 9827181979

वरिष्ठ आईएएस और स्वास्थ्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन अमित कटारिया की छवि एक रफ-टफ अधिकारी की है। IAS कटारिया की तुनकमिजाजी के बहुत से किस्से हर जुबान पर है। मातहत अफसर कर्मी तो उनके केबिन में जाने से भी घबराते है। उनसे लोगों के खौफ़ खाने की जो भी वज़ह हो लेकिन इस बार उनके इस रवैये के शिकार रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल हो गए हैं। प्रदेश के दिग्गज नेता और संसदीय ज्ञान और क्षमता से बड़े बड़े अफसर भी घबराते है, उन्हीं बृजमोहन से अब अमित कटारिया भिड़ गए हैं। कौन गलत है और कौन सहीं इसका दावा हम नहीं करते। लेकिन, फिलहाल तेज तर्रार रायपुर सांसद ने मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर लोकसभा तक प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव वरिष्ठ IAS अमित कटारिया के आचरण, दुर्व्यवहार और प्रशासनिक कदाचार की शिकायत की है। बावजूद इसके आईएएस कटारिया की ईमानदारी, प्रशासनिक कार्यशैली और प्रभावी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद आमजनों पत्रकारों से उनका व्यवहार अच्छा ही रहा है। ऐसे मे पूरे मामले को लेकर प्रदेश में राजनेता बनाम नौकरशाह के इगो का यह मामला अब खासी चर्चा में है।

**शहर सत्ता/रायपुर।** हाल ही में नौकरशाहों पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने नाराजगी जाहिर की थी। अब बीजेपी के वरिष्ठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसर के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष और सचिवालय से लेकर कार्मिक विभाग तक मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव, 2004 बैच के IAS अमित कटारिया पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की और श्री कटारिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना भी लोकसभा को दी है। शिकायत पत्र और लोकसभा सचिवालय के पत्र की प्रतियों के मुताबिक, बृजमोहन अग्रवाल का आरोप है कि अमित कटारिया ने उनसे कहा – 'जो करना है कर लो!'

बृजमोहन अग्रवाल को शिकायत थी कि जनहित से जुड़े मामलों और प्रशासनिक बातों को लेकर अमित कटारिया उनकी चिट्ठियों और स्मरण पत्रों का जवाब नहीं देते। ऐसा कई महीनों से चल रहा था। उन्होंने कहा कि यह एक निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रति एक अफसर का गैरजिम्मेदाराना रवैया था। एक प्रशासनिक अफसर के रूप में यह अमित कटारिया की अपनी जवाबदेही के प्रति उदासीनता थी। अगले दिन, 21 मई को लोकसभा अध्यक्ष को दी गई अपनी औपचारिक शिकायत में उन्होंने लिखा – 'लगातार गैर जवाबदेही का यह रवैया संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत उनके विशेषाधिकार हनन और केंद्र सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2011 और 13 सितंबर 2022 को जारी प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों का सरासर उल्लंघन है।' करीब ढाई महीने पहले 20 मई को यह विवाद तब गंभीर हो गया जब बृजमोहन अग्रवाल के मुताबिक अमित कटारिया ने कथित रूप से फोन पर उनसे वह विवादित बात कह दी।

### लोकसभा अध्यक्ष से संज्ञान लेने का किया आग्रह

बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी शिकायत में लिखा है कि यदि एक लोकसभा सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है तो इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि आम नागरिकों के साथ इस अफसर का व्यवहार कैसा होगा। उन्होंने यह भी लिखा कि इस अफसर के विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें आती रहीं हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले का गंभीरता के साथ संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए नियम 227 के तहत मामला विशेषाधिकार समिति को भेजे जाने की मांग की है। साथ ही अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 18 या केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम के नियम 20 के तहत कार्मिक विभाग से स्वास्थ्य सचिव के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग की है।

## सीएम को इसकी जानकारी है या नहीं, पता नहीं

इस बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि सांसद ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी इस मामले की शिकायत की है या नहीं। उल्लेखनीय है अमित कटारिया कुछ बरस प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में काम कर हाल ही में अपने कैडर वाले राज्य छत्तीसगढ़ लौटे हैं। प्रशासन में अमित कटारिया की छवि एक सख्त मिजाज अफसर की है। लेकिन उनका विवादों से नाता पुराना है।

## प्रशासनिक हलकों में पसरा सन्नाटा

इस मामले में स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया का पक्ष जानना चाहा साथ ही इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव विकास शील से भी संपर्क करने की कोशिश की। फिलहाल दोनों से ही संपर्क नहीं हुआ। समाचार लिखे जाने तक राज्य शासन और चीफ सेक्रेटरी से किसी भी तरह का जवाब नहीं आया है।

## सांसद की शिकायत में घटना का ये है ब्योरा

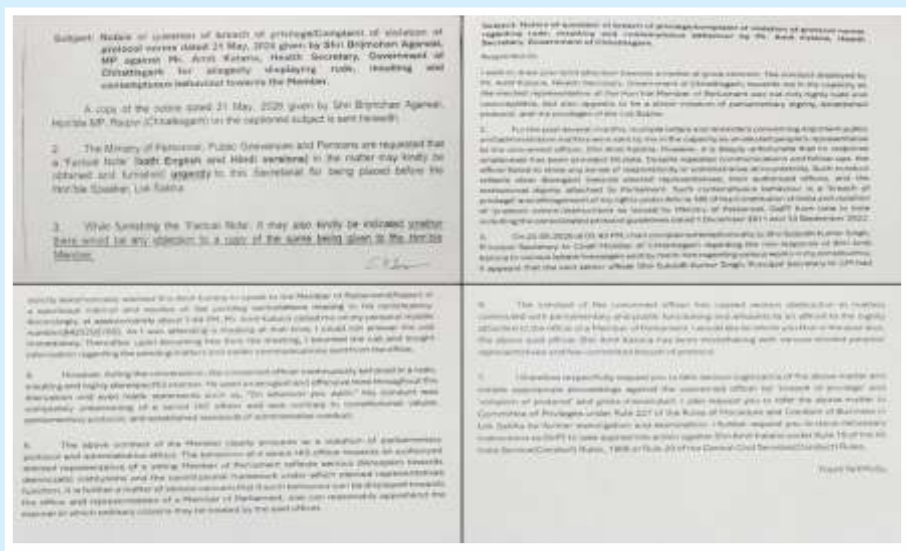

बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी शिकायत में इस घटना का जो ब्योरा दिया है उसके मुताबिक उन्होंने 20 मई की शाम 5:43 बजे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को फोन कर स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया की इस निष्क्रियता के खिलाफ शिकायत की। इस पर सुबोध सिंह ने तत्काल अमित कटारिया को फोन पर ही निर्देशित किया कि वे सांसद से तुरंत बात करें और उनके संसदीय क्षेत्र से जुड़े सारे मुद्दों को हल करें। अमित कटारिया ने 7:44 बजे बृजमोहन अग्रवाल को फोन किया। तब श्री अग्रवाल व्यस्तता की वजह से उनका फोन रिसीव नहीं कर पाए लेकिन जैसे ही उन्हें फुर्सत मिली उन्होंने तुरंत अमित कटारिया को कॉल बैक किया। श्री अग्रवाल की शिकायत के मुताबिक उन्होंने श्री कटारिया से अपने सभी लंबित मामलों की स्थिति जाननी चाही। उनका कहना है कि इस पूरे संवाद के दौरान अमित कटारिया बेहद रूखे, अपमानजनक और अत्यंत अनादरपूर्ण लहजे में बात कर रहे थे। उन्होंने पूरी बातचीत में अहंकारपूर्ण और अमर्यादित ढंग से बात की। बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि अमित कटारिया ने उनसे यहां तक कहा – 'जो करना है कर लो!' उन्होंने कहा कि श्री कटारिया का यह व्यवहार वरिष्ठ आईएएस अफसर से अपेक्षित आचरण के विपरीत और संवैधानिक मूल्यों, संसदीय प्रोटोकॉल और स्थापित प्रशासनिक आचरण के खिलाफ था।

### लोकसभा सचिवालय ने मंगाई है जानकारी

लोकसभा सचिवालय ने कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को पत्र भेजकर मामले पर अंग्रेजी और हिंदी, दोनों भाषाओं में 'फैक्चुअल नोट' अविलंब उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि इसे लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा जा सके। सचिवालय ने यह भी पूछा है कि क्या इस नोट की एक प्रति सांसद को भी दी जा सकती है।

## 2015 में भी विपरीत आचरण की मिली थी नोटिस

बात 2015 की है और संयोग से वह भी मई का ही महीना था। तब 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर दौरे पर आये थे। तब श्री कटारिया बस्तर कलेक्टर थे और इस नाते प्रधानमंत्री की उन्होंने अगवानी की लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने आंखों पर धूप का काला चश्मा पहना हुआ है और इसे गरिमा के प्रतिकूल माना जाएगा। तब राज्य सरकार ने उन्हें आचार संहिता के विपरीत आचरण करने के लिए सचेत करते हुए नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में कहा गया था कि इस प्रकार का कोई भी कृत्य भविष्य में ना करें जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के गरिमा के अनुरूप ना हों।

# एडीजी साब, सच जानना है तो दरबार लगाइए...

## मनमानी ड्यूटी, डीजल-पेट्रोल पर्ची में गोलमाल के लिए आरक्षक चालकों पर दबाव

- गुप्तवार्ता की वाहन शाखा में आरआई और एमटीओ से ज्यादा इमानदार हैं आरक्षक चालक
- एसबीएमटी पुल के आरक्षक चालकों के वाट्सएप ग्रुप में असंतोष और शिकायत आम
- एडीजी, डीआईजी, एआईजी इंट के दरबार में पुरे घोटाले का काला सच्च बताने सब तैयार

पुलिस वाहन शाखा के हवलदार और आरक्षक चालक बड़ी शिद्दत से बड़े साहब के दरबार की बाट जोह रहे हैं। वजह साफ़ है साहब, आरक्षक चालक पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करना और एसबीएमटी पुल में पदस्थ डीएसपी, आरआई और एमटीओ द्वारा दबाव पूर्वक किये जा रहे बर्ताव की शिकायत करना चाहते हैं। पुलिस के छोटे कर्मचारियों में अफसर को लेकर यदा-कदा गुस्सा खतरनाक तरीके से फुट पड़ता है। ऐसे कई जानलेवा उदाहरण रायपुर पुलिस के जेहन में ताज़ा हैं। कमोबेश यही आलम पुलिस लाइन रायपुर स्थित एसबीएमटी पुल का है। गंभीर अनियमित्ता और शासकीय वाहनों के नाम से हजारों लीटर डीजल-पेट्रोल का गोलमाल कर जेब भरने वाले अफसरों के दबाव में है आरक्षक चालक संवर्ग।

**शहर सत्ता/रायपुर।** छत्तीसगढ़ पुलिस की गुप्तवार्ता के मातहत एसबीएमटी पुल में पुरे सिस्टम की बजी पड़ी है। वहान शाखा के अफसर आरक्षक चालकों को करप्शन करने बोलते हैं। बात नहीं मानने पर गन्दी गालियां देते हैं। जो गलियों का करता है उन्हें सुबह से रात तक ड्यूटी के नाम पर बुलाकर पुरे समय बिठाये रखते हैं। अगर किसी की मुख्यालय से छुट्टी स्वीकृत हो भी गई तो अफसर उन्हें छोड़ते ही नहीं। चौंकाने वाली बात यह कि खड़ी सरकारी गाड़ियों के नाम पर डीजल पर्ची और पेट्रोल के नाम पर अपनी निजी गाड़ियों में फ्यूल डालने मजबूर करते हैं। विशेष शिक्षा के आरक्षक चालकों से अपने घर की गाड़ी चलने और बीवी-बच्चों की ड्यूटी लिए दबाव डालते हैं।

सरकारी पैसों से लेकर विभागीय नियमों की धज्जियाँ उड़ने वालों की अगर कोई शिकायत करना चाहता है तो उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। आरक्षक चालकों के मुताबिक हमें सीधे मुख्यालय के अधिकारीयों से शिकायत पत्र देने के लिए भी इन्हीं अफसरों के माध्यम से जाना पड़ता है। इसलिए इन सब से तंग आकर एसबीएमटी पुल के आरक्षक चालक अपने वाट्सएप ग्रुप में ही भड़ास निकाल रहे हैं। एक दूसरे को समझाने से लेकर एडीजी गुप्तवार्ता अमित कुमार या फिर डीआईजी आजातशत्रु बहादुर सिंह से मिलकर अपनी व्यथा बयान करना चाहते हैं।

### सब की सुनते हैं तो इनकी भी सुन लीजिए

शासन-प्रशासन के लिए पुलिस का गुप्तवार्ता ऐसा इदारा है जिसके कन्धों पर महती है। सरकार की आंख-नाक और कान कहलाने वाले इस महकमे ने अपने ही विभागीय स्टाफ से ऐसे मुंह मोड़ लिया है इसलिए मझोले अधिकारी निरंकुश हो गए हैं।

एटीएस, एसबी, एसआईबी और एसबीएमटी पुल के अलावा वीआईपी सुरक्षा की महती जिम्मेदारी है इन पर। लेकिन सबसे राहत भरी बात है प्रदेश से नक्सलवाद के खात्मे के बाद गुप्तवार्ता में छोटे अफसर-कर्मचारी से आला अधिकारीयों ने मुंह मोड़ लिया है। जबकि माओवाद के चरम पर और वीआईपी आगमन पर पूरा स्टाफ मिलकर काम करता रहा है। महकमे के मातहत चाहते हैं एडीजी इंट अमित कुमार विभागीय दरबार लगाएं और हमारे सुख-दुख को बांटे।

### केस 1

ऐसे कई साक्ष्य और SB/MT पुल में अनियमताओं की खबरें भरी पड़ी हैं। जैसे हाल ही में दिनांक 28-7-2026 को CG 03 5921 सूमो वाहन के नाम से पर्ची कटी लेकिन उस तारीख को वाहन कवर्धा में थी। इसी गाड़ी के नंबर से डीएसपी की प्राइवेट स्कॉर्पियो में 25 लीटर डीजल डाला गया।

### केस 2

**खड़ी बुलेट प्रुफ गाड़ी भी पी गई 25 लीटर**

एसबी एमटी पुल में खड़ी बुलेट प्रुफ स्कार्पियो क्रमांक सीजी-03- 6207 में 30 मई को 25 लीटर डीजल पर्ची जारी हुई। बता दें इस वहां का चालक आनंद जगत है लेकिन स्कॉर्पियो पुल से निकली ही नहीं फिर भी आरआई सौरभ चंद्राकर ने खड़ी गाड़ी के नाम पर 25 लीटर की पर्ची जारी किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एसबी-एमटी पुल में एडीजी अमित कुमार की नाक के नीचे उनके मातहत कितनी भर्राशाही कर रहे हैं।

### प्रमुख बिंदु

- पुलिस लाइन स्थित पुराने एमटी वर्क शॉप में संचालित एसबी-एमटी पुल अंतर्गत CM हॉउस, एसीबी, एसबी, प्रदेश के समस्त वीआईपी वाहनों और रिजर्व कोटे(40 गाड़ियां) की गाड़ियों को मिलाकर सैकड़ों डीजल-पेट्रोल वहान हैं। पेट्रोल-डीजल वाहनों की आपूर्ति एसबी-एमटी पुल से होती है। रायपुर एसबी-एमटी पुल से इनके लिए रोजाना औसतन 50 गाड़ियों में फ्यूल के लिए पर्ची आरआई एसबी-एमटी पुल प्रभारी सौरभ चंद्राकर जारी करते है।
- 40 से 50 वाहनों के लिए जारी होने वाला पेट्रोल डीजल का प्रतिदिन का कोटा औसतन प्रति गाड़ी 40 से 50 लीटर या आवश्यकता अनुसार पर्ची जारी की जाती है। अगर 50 से गुणित करें तो आंकड़ा प्रतिदिन 2000 लीटर होता है। वाहनों में नवा रायपुर स्थित एक निजी पेट्रोल पंप और रायपुर के जनसेवा पुलिस पेट्रोल पंप अमलेश्वर बटालियन से फ्यूल भरवाया जाता है।

### रोजाना 200 लीटर फ्यूल की अफरा-तफरी

पुलिस विभाग में एसबी-एमटी पुल में गोपनीय कार्य के नाम पर, नवा रायपुर पीएचक्यू आने-जाने और एसबी-एसआईबी, सीएम हॉउस के अलावा वीआईपी ड्यूटी के नाम पर धड़ल्ले से चल रहा पेट्रोल-डीजल घोटाले का यह खेल रोजाना 50 गाड़ियों में तकरीबन 2000 लीटर डीजल-पेट्रोल का 1 लाख 90 हजार रूपये होता है। ऐसे में प्रति गाड़ी वाहन चालक को 40 या उससे अधिक फ्यूल पर्ची जारी करने के 200 रूपये कमीशन वसूली के अलावा पंप से प्रति लीटर 5 रूपये बतौर कमीशन लिए जाने की खबर है।

### गुप्तवार्ता के सभी अफसरों को शिकायत

एडीजी गुप्त वार्ता अमित कुमार, डीआईजी एमएल कोटवानी समेत एआईजी इंट ज्ञानेंद्र कुमार अवस्थी को भी एसबी-एमटी पुल रायपुर में चल रही अनियमितताओं की लिखित और मौखिक शिकायतें की गई हैं। फ़िलहाल महकमे के आला अफसर मामले पर जांच कर रहे हैं। लेकिन आरोपियों से पूछताछ और कार्रवाई अब तक सिफर है।

### एसबीएमटी पुल के जिम्मेदार ये कहते हैं

डीएसपी एसबी शाखा मणिशंकर चंद्रा से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। वाट्सएप में भी उनसे उनका पक्ष जानना चाहा पर समाचार लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया था। आरआई एसबीएमटी पुल प्रभारी सौरभ चंद्राकर का कहना है आरोप झूठा बेबुनियाद है। आप को जो भी जानकारी चाहिए एमटी पुल आइये वहीँ बात करेंगे। एमटीओ प्रेमकांत त्रिवेदी से जब फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।

# अब नहीं मिलेगी 'तारीख पर तारीख'!

**डिजिटल जस्टिस का बड़ा संकल्प, तीन साल के भीतर फैसले का दावा**

## स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कहा— आम नागरिक को न्याय दिलाना नए कानूनों का मूल उद्देश्य

**रायपुर।** तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, फिल्मों का यह मशहूर डायलॉग अब सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित रहे, यही संकल्प छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है. रायपुर में आयोजित "स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस" राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री विजय शर्मा और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने न्याय व्यवस्था को डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का रोडमैप पेश किया. सरकार का दावा है कि भविष्य में किसी भी आपराधिक मामले के फैसले में तीन साल से अधिक का समय नहीं लगेगा.

रायपुर के एक निजी होटल में "स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस" विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव, न्यायमूर्ति चंद्रवंशी, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सभी जिलों के एसपी, आईजी, डीजीपी, न्यायिक अधिकारी और पुलिस एवं अभियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

### तारीख पर तारीख अब इतिहास: विजय शर्मा

अपने संबोधन की शुरुआत गृहमंत्री विजय शर्मा ने फिल्म के चर्चित डायलॉग तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख से की.उन्होंने कहा कि यह संवाद वर्षों से आम लोगों की न्याय व्यवस्था को लेकर बनी धारणा को दर्शाता है, लेकिन अब इस सोच को बदलने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, पुलिस और अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो चुका है।

### तीन साल के भीतर फैसले का दावा

गृहमंत्री विजय शर्मा ने विश्वास जताया कि कार्यशाला के बाद न्याय व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी.उन्होंने कहा कि भविष्य में जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी आपराधिक मामले के फैसले में तीन साल से अधिक का समय नहीं लगेगा. उन्होंने बताया कि नए तीन आपराधिक कानूनों का उद्देश्य भी लोगों को समयबद्ध, प्रभावी और पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराना है.

### बदल गई न्याय व्यवस्था की सोच: सीएम

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किए गए नए आपराधिक कानून पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू किए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि पुलिस, अभियोजन और न्यायिक अधिकारियों को नए कानूनों का प्रशिक्षण देकर उन्हें तेजी से जमीन पर लागू किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने कानून उस दौर के थे, जब न सीसीटीवी कैमरे थे और न ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का महत्व था, इसलिए आधुनिक अपराधों की जांच में कई व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आती थीं.

### डिजिटल एविडेंस और फॉरेंसिक होंगे सबसे बड़े हथियार

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों में डिजिटल एविडेंस को स्पष्ट कानूनी मान्यता दी गई है. अब सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य अपराधों की जांच में अहम भूमिका निभाएंग. उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक साइंस में हुई प्रगति से अपराधियों को सजा दिलाने में काफी मदद मिलेगी और वैज्ञानिक जांच से न्याय प्रक्रिया अधिक मजबूत बनेगी. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि नए तीनों आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य की न्याय व्यवस्था अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक, त्वरित और तकनीक आधारित बनेगी. उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लेकर आए हैं।

# 1.60 लाख शिक्षक एलबी संवर्ग को झटका

## पहली नियुक्ति यानी 2008 से नहीं जुड़ेगी सेवा, 1 जुलाई 2018 से ही मिलेगा पेंशन का लाभ

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ के करीब 1.60 लाख शिक्षक (एलबी) संवर्ग के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन और दूसरे सेवा लाभों की गणना शिक्षाकर्मी के रूप में पहली नियुक्ति की तारीख से नहीं होगी। इसके लिए 1 जुलाई 2018 को ही आधार माना जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर शिक्षकों की मांग को खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पहले कई शिक्षक शिक्षाकर्मी के रूप में पंचायत और नगरीय निकायों के तहत काम करते थे। बाद में सरकार ने उनका 1 जुलाई 2018 को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन (सरकारी विभाग में शामिल) किया। कुछ शिक्षकों की मांग थी कि पेंशन और दूसरी सुविधाओं के लिए उनकी सेवा की गिनती पहली नियुक्ति की तारीख से की जाए, क्योंकि वे उससे पहले भी कई साल नौकरी कर चुके थे।

सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि-शिक्षक (एलबी) संवर्ग के सभी सेवा लाभों की गणना 1 जुलाई 2018 से ही होगी। इससे पहले की नौकरी को शासकीय सेवा नहीं माना जाएगा। इसलिए पहली नियुक्ति से सेवा जोड़कर पेंशन या अन्य लाभ नहीं दिए जा सकते। उदाहरण के लिए किसी शिक्षक की शिक्षाकर्मी के रूप में नियुक्ति 2008 में हुई। उनका संविलियन 1 जुलाई 2018 को हुआ। यदि वे 2038 में रिटायर होते हैं, तो सरकार उनकी पेंशन के लिए सेवा 2008 से नहीं, बल्कि 2018 से मानेगी। यानी 30 साल नहीं, 20 साल की सरकारी सेवा मानी जाएगी।

मान लीजिए दो शिक्षक हैं—शिक्षक A की नियुक्ति 2007 में शिक्षाकर्मी के रूप में हुई। शिक्षक B की नियुक्ति 2010 में हुई। दोनों का संविलियन 1 जुलाई 2018 को हुआ। सरकार के नए फैसले के मुताबिक, दोनों की सरकारी सेवा की शुरुआत 1 जुलाई 2018 से ही मानी जाएगी।

### हाई कोर्ट ने क्या कहा था?

यह मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पहुंचा था। शिक्षकों ने मांग की थी कि उनकी सेवा पहली नियुक्ति से जोड़ी जाए। 23 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह मामले पर संवैधानिक और मानवीय पहलुओं को देखते हुए उचित फैसला ले। इसके बाद सरकार ने अपना निर्णय जारी करते हुए मांग खारिज कर दी। सरकार का कहना है कि 1 जुलाई 2018 से पहले शिक्षक पंचायत और नगरीय निकाय के कर्मचारी थे। वे सीधे राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं थे। इसलिए उस अवधि को शासकीय सेवा मानकर पेंशन की गणना नहीं की जा सकती। इस फैसले से उन शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है, जो चाहते थे कि उनकी पूरी नौकरी की अवधि पेंशन में जोड़ी जाए। हालांकि, हाई कोर्ट ने पहले ही कहा था कि यदि शिक्षक सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। तो वे फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे में इस मामले पर आगे कानूनी लड़ाई की संभावना बनी हुई है।

## बिना सहमति स्मार्ट मीटर लगाया गया अब बदलने की मांग पर आनाकानी क्यों?

**शहर सत्ता/रायपुर।** प्रदेस कॉंग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा बताये स्मार्ट मीटर बनाने वाली कम्पनियों से क्या सांठगांठ है? स्मार्ट मीटर कम्पनियों से कितना चंदा लिया जो स्मार्ट मीटर के बचाओ में जनता की मांग के खिलाफ स्मार्ट मीटर के पक्ष में बात कर रहे है?भाजपा को अनाप शनाप बिजली बिल से हो रही जनता की लूट दिख नही रही है। क्योंकि स्मार्ट मीटर खरीदी में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है?स्मार्ट मीटर से हो रही लूट में भाजपा भी भागीदार है?स्मार्ट मीटर अविश्वनीय है जनता को भरोसा नही है ऐसे में बिजली कम्पनी मनमानी करने के बजाये जनता की मांग पर स्मार्ट मीटर बदलने की कार्यवाही करें। जनता से पूछकर सहमति ले कर स्मार्ट मीटर तो नही लगाया गया है। बल्कि गुमराह कर गैंग भेजकर स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाया गया है। अब जब जनता स्मार्ट मीटर बदलना चाह रही है तो कम्पनी किंतु परन्तु करने के बजाये स्मार्ट बदलने की कार्यवाही शुरू करे।

## राज्य में प्रशासनिक अराजकता पर कांग्रेस का तंज

**शहर सत्ता/रायपुर।** प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता हावी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि स्थितियां इतनी बदतर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल को एक वरिष्ठ अधिकारी कहता है, जो करना है कर लो। सोचिये जब बृजमोहन जैसे नेता की यह स्थिति है तो राज्य के अन्य विधायकों की जनप्रतिनिधियों की क्या सुनवाई होती होगी। वरिष्ठ भाजपा नेता ननकी राम कंवर बिचारे तो प्रशासनिक अराजकता के खिलाफ धरना प्रदर्शन तक कर चुके है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के एक वरिष्ठ सचिव के द्वारा राज्य के सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठतम नेता को खुलेआम धमकी प्रदेश सरकार की बेचारगी को बताता है। सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि में इतनी क्षमता नहीं बची है कि वे नौकरशाहों से सामान्य शिष्टाचार का पालन करना सिखा सके। सांसद बृजमोहन के साथ घटी घटना अकेली नहीं है, राज्य में आज बेलगाम लाल फीता शाही के सांसद के सामने जन प्रतिनिधि बौने हो गये है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है, बेमेतरा में मुख्यमंत्री के समक्ष सरकारी कार्यक्रम में अव्यवस्था पसरी है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को मंच से रोष प्रकट करना पड़ता है।

## व्यावसायिक शिक्षा की किताबें डेढ़ महीने बाद भी गायब : राजपूत

**शहर सत्ता/रायपुर।** कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों ने प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका दिया है। एक ओर सरकार नई शिक्षा नीति और कौशल विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, दूसरी ओर व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों को सत्र शुरू होने के डेढ़ महीने बाद भी सरकारी पुस्तक उपलब्ध नहीं करा सकी। यह सरकार की घोर लापरवाही, अकर्मण्यता और शिक्षा के प्रति असंवेदनशील रवैये का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रदेश के लगभग 1244 शासकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है। पिछले 8 से 10 वर्षों से यह योजना चल रही है, फिर भी सरकार समय पर किताबें उपलब्ध नहीं करा पाई। 15 ट्रेडों की पुस्तकें आज तक विद्यालयों में नहीं पहुंची हैं। आखिर बिना पुस्तकों के विद्यार्थी पढ़ाई कैसे करेंगे? क्या भाजपा सरकार विद्यार्थियों को केवल घोषणाओं के सहारे शिक्षा देना चाहती है?प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसी योजना की हालत बदतर है। सरकार के दावे पूरी तरह खोखले साबित हो चुके हैं।

# नशामुक्त भारत के संकल्प के साथ पत्रकारिता विश्वविद्यालय में शपथ

**रायपुर।** कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में 'नशा मुक्त युवा अभियान' के अंतर्गत रविवार को शपथ ग्रहण किया गया और उपस्थित जनसमूह ने नशा मुक्त रहने तथा समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो मनोज दयाल ने युवाओं से जीवन में अनुशासन, आत्मसंयम एवं सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की प्रसिद्ध पंक्ति "जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है" का उल्लेख करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के विवेक, परिवार और भविष्य—तीनों को नष्ट कर देता है। उन्होंने विद्यार्थियों से मोबाइल का भी संयमित एवं सार्थक उपयोग करने का आग्रह किया तथा विश्वविद्यालय परिसर को पूर्णतः नशा मुक्त कैंपस बनाने की घोषणा की। कुलसचिव सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि जीवन में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले उसका आर्थिक एवं सामाजिक विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। नशे की शुरुआत क्षणिक सुख के लालच से होती है, लेकिन कब यह आदत लत में बदल जाती है, इसका पता नहीं चलता।

कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष पंकज नयन पांडेय, डॉ नृपेन्द्र शर्मा, डॉ राजेन्द्र मोहंती सहित अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने 'नशा मुक्त भारत' के निर्माण में सक्रिय योगदान देने तथा स्वयं नशे से दूर रहने की शपथ ली। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन डॉ. शैलेन्द्र खंडेलवाल ने किया।

## आतंकी हमले में मृत मजदूरो के शव उनके घरो तक नहीं लाना सरकार की असंवेदनशीलता : दीपक बैज

**शहर सत्ता/रायपुर।** प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में मारे गये छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों का शव छत्तीसगढ़ नहीं लाना तथा वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाना भाजपा सरकार की असंवेदन शीलता को दिखाता है। एक तो डबल इंजन की सरकार हमारे मजदूरों को सुरक्षा नहीं दे पाई, ऊपर से उनकी मौत के बाद उनके किया कर्म के लिये उनके शवो को घरों तक नहीं पहुंचाना बताता है कि भाजपा सरकार की नजर में छत्तीसगढ़ के मजदूरों की कोई अहमियत नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की आतंकियों ने हत्या कर दिया। एक सारंगढ़ के थे एक सक्ति के थे। हमारी छत्तीसगढ़ की नकारी सरकार मजदूरों के शव भी उनके घरो तक नहीं ला पाई उनका वही अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्या यह डबल इंजन सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि मृतकों के शव उनके घर पहुंचाए।

शर्म आती है ऐसी सरकार पर। मुआवजा भी छग सरकार ने मात्र 20 लाख घोषित किया है जबकि 1 करोड़ देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आतंकी हमले में मारे गए नागरिकों को उनकी मौत के बाद भी यथोचित सम्मान नहीं दे पा रही। उन दोनों मृतकों का शव इसलिये नहीं लाया गया, क्योंकि वे मजदूर थे? मुख्यमंत्री और सरकार इसका जवाब दे।

## छत पर देर रात गाना बजाने पर लड़कियां गिरफ्तार

**रायपुर।** रायपुर के गांधीनगर कालीबाड़ी इलाके में देर रात छत पर तेज आवाज में गाने बजाकर पार्टी करना 7 युवक-युवतियों को भारी पड़ गया। रात करीब 3 बजे तेज साउंड सिस्टम की शिकायत पर पहुंची पुलिस के साथ कथित धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 3 युवतियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस के मुताबिक, घटना प्रताप तांडी के मकान की छत पर हुई, जहां बर्थडे पार्टी चल रही थी। आसपास के लोगों ने तेज आवाज में गाने बजने और हंगामे की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस पहली बार मौके पर पहुंची तो मौजूद लोगों को समझाइश देकर साउंड सिस्टम बंद करा दिया गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर उसी जगह से तेज आवाज में गाने बजने की शिकायत मिली। इस पर पुलिस टीम दोबारा मौके पर पहुंची। पुलिस का आरोप है कि दूसरी बार साउंड सिस्टम बंद कराने पर वहां मौजूद युवक-युवतियों ने पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की।

# अरुण मालाकार पर कार्रवाई के बाद कांग्रेस में बढ़ी खींचतान

**शहर सत्ता/रायपुर।** छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष (PCC) की नियुक्ति को लेकर चल रही सियासत अब खुलकर सामने आने लगी है। वरिष्ठ नेता उमेश पटेल के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट करना सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरुण मालाकार को भारी पड़ गया। प्रदेश कांग्रेस ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद पार्टी के भीतर नया विवाद खड़ा हो गया है। नोटिस जारी होते ही कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कार्रवाई पर नाराजगी जताई। इसके बाद संगठन के फैसले को लेकर पार्टी के अंदर अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

### पहले भी पोस्ट हुए, लेकिन एक्शन नहीं हुआ

एक पक्ष इसे अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है कि जब पहले भी कई नेताओं के समर्थन में खुले तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट और अभियान चलते रहे हैं, तब संगठन ने ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की।

### उमेश पटेल के समर्थन वाली पोस्ट पर नोटिस

अरुण मालाकार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता उमेश पटेल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के समर्थन में पोस्ट साझा की थी। पोस्ट वायरल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। संगठन का कहना है कि पार्टी के किसी भी पद को लेकर सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया अभियान चलाना संगठन की आंतरिक प्रक्रिया के खिलाफ है। इसी आधार पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर प्रभारी महामंत्री ने नोटिस जारी किया।

## नाबालिग से कार में दुष्कर्म, दो बार किया रेप

**रायपुर।** रायपुर की पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी प्रेमलाल निषाद (20) को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी माना। मामला अभनपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 4 अक्टूबर 2025 की रात करीब 10:30 बजे नाबालिग अपने घर से बिना बताए चली गई थी। अगले दिन सुबह वह घर लौटी, लेकिन डरी होने के कारण उसने परिवार को कुछ नहीं बताया। करीब तीन दिन बाद 8 अक्टूबर को पीड़िता ने परिवार को बताया कि गांव का रहने वाला प्रेमलाल निषाद उसे घुमाने के बहाने चार पहिया वाहन में बैठाकर ले गया था। आरोप है कि सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों रातभर वाहन में रहे। अगले दिन वाहन खराब होने पर आरोपी उसे बाइक से अपनी नानी के घर ले गया और कुछ देर बाद पीड़िता को उसके घर छोड़ दिया। डर की वजह से पीड़िता ने तत्काल घटना की जानकारी नहीं दी। परिवार की शिकायत पर अभनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता और आरोपी के कपड़े जब्त किए, मेडिकल परीक्षण कराया और घटना में इस्तेमाल किए गए बोलेरो पिकअप और बाइक को भी जब्त किया।

# E20 पेट्रोल के खिलाफ AAP का दिल्ली मार्च

## प्रदेश से हजारों कार्यकर्ता 4 अगस्त को घेरेंगे पीएम आवास

**रायपुर।** आम आदमी पार्टी (AAP) 4 अगस्त को केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर होने वाले इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। A A P छत्तीसगढ़ के मुताबिक, प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों से करीब 50-50 कार्यकर्ताओं को दिल्ली भेजने की तैयारी की गई है। पार्टी का दावा है कि छत्तीसगढ़ से हजारों कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगे और केंद्र सरकार की E20 नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।

### E20 से गाड़ियों को नुकसान होने का दावा

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि E20 पेट्रोल नीति की वजह से वाहन मालिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी का दावा है कि इससे गाड़ियों में तकनीकी खराबी, माइलेज में कमी और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ रहा है। AAP का कहना है कि इन शिकायतों के बावजूद केंद्र सरकार नीति की समीक्षा नहीं कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ E20 पेट्रोल नीति के विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के आर्थिक हितों से जुड़ा मुद्दा है। उनका आरोप है कि बिना पर्याप्त तैयारी और व्यापक अध्ययन के इस नीति को लागू किया गया, जिससे करोड़ों वाहन मालिक प्रभावित हो सकते हैं।

### लोगों से मांगे E20 से नुकसान के वीडियो

आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं और वाहन मालिकों से अपील की है कि यदि उनकी गाड़ियों को E20 पेट्रोल से किसी तरह का नुकसान हुआ है तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करें और अरविंद केजरीवाल को टैग करें। पार्टी का दावा है कि ऐसे वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जाएगा। AAP ने कार्यकर्ताओं से 4 अगस्त के आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होकर केंद्र सरकार तक विरोध का संदेश पहुंचाने की अपील भी की है।

## संपादकीय

सुकांत राजपूत

# कायरता की सीमा और न्याय की पुकार

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में हुआ हालिया आतंकवादी हमला न केवल घाटी में शांति बहाली के प्रयासों को गहरा झटका देता है, बल्कि पूरे देश को स्तब्ध और आक्रोशित करता है। निर्दोष और मेहनतकश नागरिकों को निशाना बनाकर खेला गया यह खूनी खेल आतंकवादियों की बढ़ती हताशा और कायरता का ही नग्न प्रदर्शन है। जब बंदूक की नोक पर अपनी आजीविका कमाने आए निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो यह किसी विचारधारा का संघर्ष नहीं, बल्कि विशुद्ध बर्बरता और घृणित मानसिकता का प्रतीक बन जाता है।

इस नृशंस हमले का सबसे दर्दनाक और हृदयविदारक पहलू छत्तीसगढ़ के उन निर्दोष श्रमिकों की शहादत है, जो अपने परिवारों का पेट पालने, बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना संजोने और रोजी-रोटी की तलाश में अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर कश्मीर गए थे। वे अपने पसीने से देश के अवसंरचनात्मक विकास में योगदान दे रहे थे। अपनी मेहनत पर भरोसा करने वाले इन गरीब और लाचार मजदूरों का आखिर क्या कसूर था? एक झटके में कई परिवारों के चिराग बुझ गए और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में मातम पसर गया। रोजी-रोटी की तलाश में निकले बेटों, पतियों और पिताओं के शव जब उनके पैतृक गांवों में लौटेंगे, तो उन परिवारों के घाव शायद ही कभी भर पाएंगे।

कुलगाम की यह घटना इस बात की ओर भी स्पष्ट इशारा करती है कि घाटी में जब-जब सामान्य स्थिति बहाल होने लगती है, पर्यटन और व्यापार गति पकड़ता है, तब-तब सीमा पार से संचालित आतंकवादी संगठन बौखला उठते हैं। अपनी साख बचाने और दहशत का माहौल कायम रखने के लिए वे अब 'सॉफ्ट टारगेट' यानी सुरक्षा बलों से दूर, निहत्थे नागरिकों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। रणनीति स्पष्ट है—गैर-स्थानीय लोगों के मन में खौफ पैदा करना ताकि घाटी में आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाएं और देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर का जुड़ाव कमजोर पड़े।

लेकिन सवाल यह है कि कब तक बेकसूरों का खून बहता रहेगा? यह हमला हमारी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की तात्कालिक मांग करता है। घाटी में प्रवासियों की सुरक्षा के लिए जो रणनीतियां बनाई गई थीं, उनमें कहां चूक रह गई, इसका निष्पक्ष आकलन होना अनिवार्य है। केवल संवेदना व्यक्त करने और राजनीतिक बयानबाजी का वक्त अब बीत चुका है। आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले स्थानीय नेटवर्क (ओजीडब्ल्यू यानी ओवर ग्राउंड वर्करों) का पूरी तरह सफाया करना होगा जो इन हत्यारों को शरण और जानकारी मुहैया कराते हैं।

इसके साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे छत्तीसगढ़ के पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हों। केवल अनुग्रह राशि की घोषणा काफी नहीं होगी; उन परिवारों के पुनर्वास, बच्चों की शिक्षा और आजीविका के स्थायी साधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

समय आ गया है कि आतंकवाद के इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ निर्णायक और कठोरतम कार्रवाई की जाए। भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कुलगाम का यह हमला चीख-चीखकर कह रहा है कि कायरता के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अब न्याय की पुकार ही एकमात्र विकल्प है।

# संघर्ष ही सफलता की कुंजी

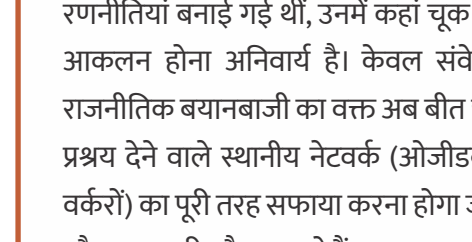

एक दूरदराज गाँव में एक मूर्तिकार रहता था। वह रोज़ पत्थरों को तराशकर सुंदर मूर्तियाँ बनाता। एक दिन उसने एक भारी पत्थर पर हथौड़े से वार करना शुरू किया। पत्थर ने दर्द से चीखकर कहा, "मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है!" मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को तराशने लगा। दूसरे पत्थर ने सारा दर्द चुपचाप सहा। कुछ दिनों में वह एक भव्य और दिव्य मूर्ति बन गया। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो सहनशील पत्थर से बनी मूर्ति को मंदिर के गर्भ गृह में स्थापित किया गया, और दर्द से डरने वाले पहले पत्थर को बाहर फर्श पर रख दिया गया, जिस पर लोग रोज़ नारियल फोड़ते थे।

# स्मार्ट प्लान: पहले बिल बढ़ाओ, फिर सोलर लगवाओ!

कॉलम - खुरचन

द्वारा- हरिदास

विकास की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जो चीज पहले साधारण थी, उसे स्मार्ट बना दिया जाता है। मोबाइल स्मार्ट हो गया, टीवी स्मार्ट हो गया, घड़ी स्मार्ट हो गई, शहर स्मार्ट हो गया और अब बिजली का मीटर भी स्मार्ट हो गया। आदमी बेचारा अभी तक स्मार्ट नहीं हो पाया। वह वही पुराना आदमी है जिसका शोषण अब स्मार्ट मीटर करने लगा है।

पहले बिजली का मीटर चुपचाप घूमता था। आदमी भी चुपचाप बिल भरता था। कभी-कभार बिल ज्यादा आता था तो बिजली विभाग के दफ्तर जाकर पूछ लेता था—"साहब, इतना बिल कैसे आ गया?"

साहब कहते थे—"बिजली ज्यादा जलाई होगी।"

आदमी कहता था—"लेकिन घर में तो हम दो ही लोग हैं।"

साहब कहते थे—"तो दो लोग मिलकर ज्यादा बिजली जलाते होंगे।"

आदमी कहता था—"साहब, हम दोनों तो दिनभर नौकरी पर रहते हैं।"

साहब कहते थे—"तो फिर रात में ज्यादा बिजली जलाते होंगे।"

आदमी निरुत्तर होकर लौट आता था।

अब स्मार्ट मीटर आ गया है। अब आदमी सवाल नहीं करता। वह बिल देखता है और चुप हो जाता है। क्योंकि स्मार्ट मीटर के सामने आदमी की बुद्धि थोड़ी कम स्मार्ट दिखाई देती है।

बिल में हजारों रुपए देखकर वह घर के सदस्यों से पूछता है-

"तुम लोगों ने बिजली कब जलाई?"

बच्चे कहते हैं—"हम तो स्कूल में थे।"

पत्नी कहती है—"मैं बाजार गई थी।"

बूढ़े पिता कहते हैं—"मैं तो दोपहर में सो रहा था।"

आदमी कहता है—"फिर बिजली किसने जलाई?"

तभी स्मार्ट मीटर अपनी डिजिटल आंखें झपकाता है और कहता है—"यह मेरा और विभाग का निजी मामला है। आप सिर्फ भुगतान कीजिए।"

सबसे ज्यादा आश्चर्य उन लोगों को हो रहा है जिनके घर बंद हैं। दरवाजा बंद है। खिड़की बंद है। पंखा बंद है। टीवी बंद है। फ्रिज बंद है। पर बिल चालू है। कभी-कभी तो लगता है कि घर में रहने वाले लोग ही गलत हैं। उन्हें घर बंद करने के बजाय बिजली का बिल बंद करना चाहिए था। एक आदमी ने बताया कि उसका मकान छह महीने से बंद है और फिर भी बिजली का बिल आ रहा है। मैंने कहा—"भाई, हो सकता है घर में कोई रहता हो।"

वह बोला—"कौन?"

मैंने कहा—"स्मार्ट मीटर।"

वह बोला—"लेकिन मीटर तो बाहर लगा है।"

मैंने कहा—"फिर तो और भी स्मार्ट है। बाहर रहकर अंदर का खर्च निकाल रहा है।"

सरकार कहती है—"सोलर लगाइए, बिजली का बिल कम कीजिए।"

जनता पूछती है—"सोलर लगवाने में कितना खर्च आएगा?"

सरकार कहती है—"पहले बिजली का बिल देखिए।"

जनता बिल देखती है। फिर सोलर की कीमत पूछती है। फिर बैंक का खाता देखती है। फिर बिजली का बिल देखती है। फिर आसमान की ओर देखती है। और अंत में कहती है—"हे सूर्य देव! अब आपकी शरण में हूं।" इस तरह बिजली का बिल धीरे-धीरे सोलर योजना का सबसे प्रभावशाली प्रचारक बन सकता है। सरकारी विज्ञापन में लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं।

बस उपभोक्ता के घर एक ऐसा बिल पहुंचा दीजिए जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। वह खुद कहेगा-"भाई, अब छत पर सूरज ही लगवा लेते हैं।"

जनता बहुत भोली है, लेकिन इतनी भी भोली नहीं कि उसे दिखाई न दे कि एक तरफ बिजली का बिल बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सोलर लगाने का संदेश जोर पकड़ रहा है।

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा बुद्धिमान वे लोग हैं जिन्होंने अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया है। वे इस समय बिजली की दुनिया के सबसे समझदार नागरिक हैं। वे दूसरों के घरों में स्मार्ट मीटर लगते देखते हैं और कहते हैं-"बहुत बढ़िया! आधुनिक तकनीक है।"

फिर धीरे से अपने मीटर की तरफ देखते हैं और कहते हैं-"तुम अभी पुराने ही ठीक हो।"

जनता में यह धारणा भी है कि बिजली विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी स्मार्ट मीटर की असली स्मार्टनेस को पहले से जानते थे। इसलिए उन्होंने अपने घरों को इस स्मार्टनेस से बचाकर रखा। हालांकि यह बात सच है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जनता का सवाल जायज है—अगर स्मार्ट मीटर इतना ही शानदार है तो इसे लगाने में किसी को डर क्यों होना चाहिए?

स्मार्ट मीटर का संदेश साफ है—"बिजली कम जलाइए, बिल ज्यादा भरिए और अंत में सोलर लगाइए! पहले बिजली का बिल देखकर आदमी परेशान होता था। अब बिल देखकर सोलर वाला खुश होता है।

स्मार्ट प्लान: पहले स्मार्ट मीटर लगाओ। फिर स्मार्ट बिल भेजो। उपभोक्ता को स्मार्ट तरीके से परेशान करो और अंत में कहो—

"अब स्मार्ट बनिए, सोलर लगाइए!"

## बातों बातों में

साप्ताहिक कॉलम

### गोदी मीडिया और पिकनिक का सीज़न!

हाल ही में, जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर सिस्टम का कहर बरपा और पत्रकारों को बेदर्दी से पीटा गया, तब दिल्ली और रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के प्रेस क्लबों ने संयुक्त निंदा प्रस्ताव पारित किए। लेकिन विडंबना देखिये, जब पत्रकार अपने साथियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उसी समय राज्य और केंद्र पोषित सरकारी खर्चे पर पत्रकारों का एक बड़ा जत्था लद्दाख और गुजरात की सैर का आनंद ले रहा था। मुफ्त की सरकारी पिकनिक, हवाई यात्रा और बड़े होटलों में मेहमानवाज़ी के शौकीन ये 'कलमवीर' अपने साथी पत्रकारों पर हुए हमले से मुंह मोड़कर सरकारी भ्रमण की फोटो-वीडियो अपलोड करने में व्यस्त रहे। आलम यह है कि अब 'खासकर संवाद और मीडिया' के लिए निष्पक्षता नहीं, बल्कि सरकार की हां में हां मिलाने वाली 'बड़ी साइज' ही मायने रखती है।

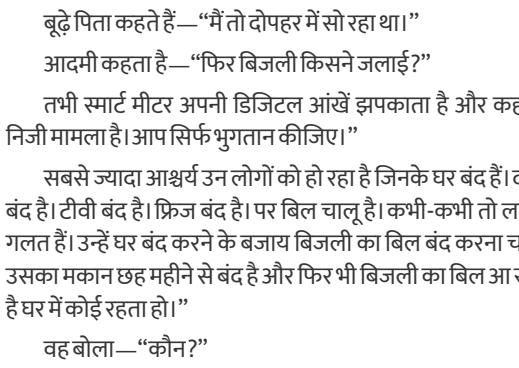


### 'संवाद' में बड़ा साइज

आज के दौर में 'साइज' का ही सारा खेल है। जिस पत्रकार का जितना बड़ा साइज (सरकार के प्रति समर्पण), उसकी उतनी ही अहमियत। नेपोलियन बोनापार्ट का दौर अब लद चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ 'संवाद' और प्रिंट मीडिया में अब छोटी नहीं, बल्कि बड़ी साइज वालों की पूछ-परख है। बातों-बातों में संवाद के एक 'हरिराम' ने बताया कि फिलहाल सबसे बड़े साइज (6.2) वाले साहब और उनके दो मातहतों (6.1 और 6) की ही 'संवाद' में तूती बोल रही है। अपवाद हर विभाग में होते हैं, यहाँ भी एक नेपोलियन बोनापार्ट था, जिसकी विदाई हो चुकी है। असली मज़ा तो अब आएगा, जब डेपुटेशन खत्म करके पुराने जनसंपर्क अधिकारी वापस लौटेंगे और पदभार के लिए यही साइज मैटर करेगा।

### गुप्त वार्ता: अब सिर्फ़ 'आरामगाह'

छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग का तरीका अब पूरी तरह बदल गया है। पहले चाल, चरित्र और चेहरा देखकर मलाईदार जिला और थाना मिलता था। सजा के तौर पर लूप लाइन भेज दिया जाता था। लेकिन अब, 'गुप्त वार्ता' भी सीआईडी की तरह ऐसे अधिकारियों की 'आरामगाह' बन गई है, जो अपनी नक्सल विरोधी लड़ाई को खत्म कर चुके हैं और अब केवल आराम चाहते हैं।

अब पुलिसिंग इसी में सिमटकर रह गई है: देर रात तक टाइमपास लोगों के साथ वक्त बिताना, दोपहर बाद दफ्तर में हाजिरी लगाना, चंद फाइलों में दस्तखत करना और फिर घर का खाना खाकर बिस्तर में शाम का इंतज़ार करना। यहाँ वर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए दिल्ली से लौटे हुए 'बड़े साहब' जो बैठे हैं!

### एक पगार, चार प्रभार

छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ IAS, विशेषकर सीएम सचिवालय के माहिर अधिकारियों से एक ही सैलरी में चार से पांच प्रभार का काम लिया जा रहा है। अरे भाई, अफसर हाड़-मांस के बने हैं, कोई 'ही-मैन' नहीं! इन पर थोड़ी रहम खाइए, इन्हें खाने तो छोड़िये, सोने का भी वक्त नहीं मिल रहा।

हाल ही में सीनियर IAS रजत बंसल जी को ही देख लीजिये। सुशासन अभिकरण, माइनिंग डायरेक्टर, माइनिंग कॉर्पोरेशन के एमडी और अब 'संवाद' के आयुक्त का प्रभार! उनका हाल देखकर खुद उनके संपादकों को भी दया आने लगी है, हालांकि 'सरकारी विज्ञापन के खौफ' से उनकी जुबान बस्तरिया मैना की तरह ही बोलती है।

### इस IAS को मंत्रीजी भी कहते हैं सर!

बात जब कामपसंद, ऊर्जावान और तेज-तर्रार IAS की होती है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी रोहित यादव की कार्यशैली सभी को याद आती है। वे प्रशासनिक 'नवरत्नों' में सबसे बेशकीमती रत्नों में एक हैं, तभी तो मंत्री भी उन्हें 'सर' कहकर संबोधित करते हैं।

रोहित यादव की काबिलियत यह है कि वे न केवल सीनियर हैं, बल्कि हर विभागीय जानकारी भी रखते हैं और जनसंपर्क सचिव भी हैं। वैसे भी, BJP सरकार में IAS लॉबी तो हमेशा ही पावरफुल रहती है। डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल से शुरू हुई यह परंपरा भूपेश बघेल के शासनकाल में भी अनवरत जारी रही। यह केवल दिवंगत अजीत जोगी ही थे, जो इन्हें डील करना जानते थे।

## 20 साल बाद कोलकाता लौटीं तसलीमा नसरीन, मचा हंगामा?

**नई दिल्ली।** तसलीमा नसरीन करीब दो दशक बाद एक बार फिर कोलकाता पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी वापसी इस बात का प्रमाण है कि अन्याय लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहता. उन्होंने यह भी कहा कि वह उस दिन का इंतजार कर रही हैं, जब किसी लेखक को अपने विचारों के कारण अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े. वहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जब भी वह राज्य आएंगी, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी.शनिवार (1 अगस्त) को कोलकाता में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में तसलीमा नसरीन ने कहा कि शहर लौटकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे वह अपने जीवन के उस हिस्से में वापस आ गई हैं जिसे वह यहां छोड़कर गई थीं. उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी लेखक को अपने विचार व्यक्त करने की वजह से निर्वासन का जीवन न जीना पड़े, यही उनकी सबसे बड़ी कामना है. तसलीमा ने कहा, "मेरी वापसी इस बात का सबूत है कि अन्याय लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन स्थायी नहीं होता. मैं उस दिन का सपना देखती हूं, जब किसी लेखक को अपने देश से निर्वासित न होना पड़े."

## रूस की राजधानी मॉस्को में बम धमाका, 3 की मौत

**मॉस्को।** रूस की राजधानी मॉस्को में शनिवार शाम को एक रेस्टोरेंट के पास हुए धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं. रूसी अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट शनिवार शाम को मध्य मॉस्को में एक महंगे रेस्टोरेंट के पास हुआ, जब एक प्राइवेट कार्यक्रम चल रहा था. घर में तैयार किया गया बम लेकर महिला पहुंची थी, धमाके में उसकी भी मौत हो गई. रॉयटर्स ने रूसी समाचार एजेंसी R I A Novostki के हवाले से बताया कि देश की नेशनल एंटी-टेररिज्म कमेटी ने बताया कि एक अज्ञात महिला कुद्रिन्स्काया स्क्वायर पर स्थित बाल्जी रॉसी रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया. महिला के पास एक इंम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवास (IED) था, जो रेस्टोरेंट में घुसने से पहले ही फट गया. धमाके में महिला के साथ उसे रोकने वाले सिक्योरिटी गार्ड और एक कस्टमर की भी मौत हो गई. रूसी अधिकारियों ने महिला की पहचान उजागर नहीं की है और न ही यह बताया कि उसने ऐसा क्यों किया. हालांकि ये भी साफ नहीं है कि उसने जान-बूझकर बम विस्फोट किया था या नही।

## पहली बार जीएसआई की कमान महिला के हाथ

**कोलकाता।** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के 176 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को महानिदेशक बनाया गया है। वर्षा अशोक अगलावे ने शुक्रवार को संगठन की 54वीं महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने असित साहा का स्थान लिया, जिन्होंने दो वर्षों तक इस पद पर कार्य किया। जीवाश्म विज्ञान (पैलियंटोलाजी) की विशेषज्ञ वर्षा अगलावे को भूविज्ञान के क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का अनुभव है। भारतीय खान ब्यूरो (आइबीएम) में कार्य करने के बाद वह वर्ष 1992 में जीएसआइ से जुड़ी थीं।

# राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं पर FIR के बाद भड़की कांग्रेस

## कहा- केंद्र सरकार असली मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है

**नई दिल्ली।** राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य सांसदों पर राम मंदिर चंदे के कथित दुरुपयोग से जुड़े विरोध प्रदर्शन को लेकर FIR दर्ज की गई है. इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि BJP के नेतृत्व वाली सरकार आरोपों पर ध्यान देने के बजाय असली मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है.वाराणसी पुलिस ने संसद परिसर में किए गए एक नाटक को लेकर साधुओं की शिकायत पर राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसके बाद उन्होंने ये बातें कहीं. पत्रकारों से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि सरकार मंदिर दान से जुड़े आरोपों को नजरअंदाज करते हुए विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने पर ध्यान दे रही है.खेड़ा ने कहा, "सांसदों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही हैं, लेकिन सरकार यह भूल जाती है कि जब दान की चोरी होती है, तो इससे भक्तों की भावनाएं भी आहत होती हैं." यह विवाद संसद में हुए एक प्रदर्शन से शुरू हुआ, जिसमें पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मंदिर के पुजारी का वेश धारण किया और अन्य विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर राम मंदिर के दान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दान पेटी को लेकर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया.इस विरोध-प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज समेत बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में शिकायतें दर्ज कराईं और विपक्षी नेताओं पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया. वाराणसी में दर्ज FIR के अलावा, दिल्ली में भी पप्पू यादव के खिलाफ एक और पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है.

पवन खेड़ा ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करने वाले राहुल गांधी के हालिया बयानों का भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि जिन राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, उन्हें इस कदम का विरोध करना चाहिए. खेड़ा ने कहा कि जो लोग अपने राज्यों को लेकर चिंतित हैं, उन्हें परिसीमन का विरोध करना चाहिए. उनके ये बयान प्रस्तावित परिसीमन बिल को लेकर फिर से शुरू हुई राजनीतिक बहस के बीच आए हैं.हाल ही में तमिलनाडु दौरे के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि परिसीमन राज्य के राजनीतिक प्रभाव को कम करने की एक कोशिश है. राहुल गांधी ने कहा, "बीजेपी परिसीमन करने की कोशिश कर रही है. परिसीमन का मकसद लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना और तमिलनाडु के लोगों की राजनीतिक ताकत छीनना है. यह बीजेपी की साजिश है जो कोई भी परिसीमन का समर्थन करता है, वह तमिलनाडु के साथ धोखा कर रहा है."

### टीएमसी ने किया राहुल का बचाव

राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य सांसदों पर राम मंदिर चंदे के कथित दुरुपयोग से जुड़े विरोध प्रदर्शन को लेकर FIR दर्ज की गई है. इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि BJP के नेतृत्व वाली सरकार आरोपों पर ध्यान देने के बजाय असली मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है.वाराणसी पुलिस ने संसद परिसर में किए गए एक नाटक को लेकर साधुओं की शिकायत पर राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसके बाद उन्होंने ये बातें कहीं. पत्रकारों से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि सरकार मंदिर दान से जुड़े आरोपों को नजरअंदाज करते हुए विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने पर ध्यान दे रही है.खेड़ा ने कहा, "सांसदों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही हैं, लेकिन सरकार यह भूल जाती है कि जब दान की चोरी होती है, तो इससे भक्तों की भावनाएं भी आहत होती हैं." यह विवाद संसद में हुए एक प्रदर्शन से शुरू हुआ, जिसमें पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मंदिर के पुजारी का वेश धारण किया और अन्य विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर राम मंदिर के दान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दान पेटी को लेकर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया।

## कुलगाम में हुई हत्याओं के बाद सुरक्षा बलों ने शुरू किया एंटी-टेरर ऑपरेशन

**श्रीनगर।** जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई हत्याओं के बाद सुरक्षा बलों ने नए सिर से एंटी-टेरर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके तहत सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले के शीरी इलाके से एक 'ओवर ग्राउंड वर्कर' को पकड़ा और उसके पास से भारी मात्रा में गैर-कानूनी हथियार और गोला-बारूद बरामद किए हैं.पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों के तहत नारवाव में ज़ंडफरान-गोरीवान क्रॉसिंग पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगाए गए एक जॉइंट नाके पर की गई. चेकिंग के दौरान गोरीवान की तरफ से आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति ने नाका पार्टी को देखते ही भागने की कोशिश की. अधिकारियों ने बताया कि सतर्क जवानों ने उसका पीछा किया और उसे मौके पर ही पकड़ लिया. आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से सुरक्षा बलों ने एक कैमोफ्लाज्ड MP-5 टाइप पिस्तौल, 10 जिंदा 9mm राउंड वाली एक मैगज़ीन, एक मोबाइल फोन और एक काला बैकपैक बरामद किया. बता दें कि गिरफ्तार ओवर ग्राउंड वर्कर की पहचान बारामूला ज़िले के शीरी इलाके के नंबलन निवासी एजाज़ अहमद गनी (स्वर्गीय मोहम्मद सुल्तान गनी के बेटे) के तौर पर हुई है. एजाज़ अहमद गनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन शीरी में FIR नंबर 37/2026 दर्ज की गई है. उसके संपर्कों और गतिविधियों का पता लगाने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसिया जांच में जुटी है.अधिकारियों ने कहा कि सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियां इलाके में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

# CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की थी साजिश!

**कोलकाता।** पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल के मामले में बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूर्वी बर्धमान से गिरफ्तार संदिग्ध हमीम मंडल लगातार पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था और दिल्ली के जंतर-मंतर में प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर हिंसा फैलाने की साजिश रच रहा था। मामले में उसकी कथित सहयोगी और गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया गया है।

### झारखंड से गिरफ्तार हुई अर्पिता सरकार

एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा ने बताया कि अर्पिता सरकार को झारखंड के साहिबगंज जिले से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तकनीकी निगरानी (सर्विलांस) के जरिए उसकी लोकेशन का पता लगाया और कार्रवाई की। इसके बाद उसे पश्चिम बंगाल ले जाया गया, जहां उससे आगे पूछताछ की जाएगी। गौरव शर्मा ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि हमीम का दिल्ली के जंतर-मंतर में प्रस्तावित प्रदर्शन से क्या संबंध था।

### बर्धमान से गिरफ्तार हुआ था हमीम मंडल

एसटीएफ के मुताबिक, इस मामले का मुख्य आरोपी हमीम मंडल पहले ही पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले से गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का आरोप है कि हमीम प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल के संपर्क में था। जांच में उसके मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों से मिले दस्तावेजों के आधार पर दावा किया गया है कि वह लगातार अपने हैंडलर्स के संपर्क में था।

## स्कूल और कॉलेज के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड पर बैन

**बेंगलुरु।** कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (FSDA) विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के 50 मीटर के दायरे में ज्यादा फैट, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। यह एडवाइजरी जुलाई में 134 स्कूलों और कॉलेजों के आस-पास मौजूद फूड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के एफएसडीए द्वारा किए गए निरीक्षणों के बाद जारी की गई है। एफएसडीए ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "जांच के दौरान खाने-पीने की चीजों की क्वालिटी, साफ-सफाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन, लेबलिंग की जरूरतों, एक्सपायर हो चुके फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन की वैधता की जांच की गई।

# CJP के 1 करोड़ रुपये की फंडिंग पर उठे सवाल

**नई दिल्ली।** सूरत के एक RTI कार्यकर्ता ने CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता की वित्तीय स्थिति की जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने CJP की ओर से बनाए गए कानूनी सहायता (लीगल डिफेंस) फंड को लेकर चुनाव आयोग और केंद्रीय GST अधिकारियों को भी पत्र लिखा है। RTI कार्यकर्ता अमित तिवारी का कहना है कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी भगवानराव दीपके की वित्तीय स्थिति की जांच की मांग की है। उनका सवाल है कि उन्होंने अपने बेटे अभिजीत दीपके की विदेश में उच्च शिक्षा का खर्च किस तरह वहन किया। मित तिवारी ने यह भी कहा कि CJP एक गैर-पंजीकृत (अनरजिस्टर्ड) संगठन है, लेकिन वह राजनीतिक दल की तरह काम कर रहा है।

### धन जुटाने या प्राप्त करने के मामले की जांच हो

उन्होंने कहा कि यदि पार्टी के लीगल डिफेंस फंड के लिए 1 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, तो चुनाव आयोग को यह जांच करनी चाहिए कि क्या CJP का पंजीकरण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि संगठन पंजीकृत नहीं है, तो राजनीतिक दल के नाम पर संचालन और धन जुटाने या प्राप्त करने के मामले की जांच की जानी चाहिए। RTI कार्यकर्ता ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC से भी अनुरोध किया है कि वह यह जांच करे कि CJP के प्रदर्शनकारियों के लिए घोषित 1 करोड़ रुपये के लीगल डिफेंस फंड पर 18 प्रतिशत GST लागू होगा या नहीं।

### कपिल सिब्बल ने किया था 1 करोड़ रुपये की घोषणा

गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोमवार को CJP द्वारा बनाए गए लीगल डिफेंस फंड में 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। यह फंड NEET पेपर लीक मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामलों का सामना कर रहे प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है।

### वीजा से पहले 20,000 डॉलर तक का बॉन्ड जमा करना पड़ेगा

# US के नए वीजा नियम ने बढ़ाई चिंता

**वाशिंगटन** अमेरिका ने अपने वीजा बॉन्ड प्रोग्राम को स्थायी बना दिया है. इसके तहत कॉन्सुलर अधिकारी बिज़नेस और टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन करने वाले कुछ विदेशी नागरिकों से वीजा जारी करने से पहले 20,000 डॉलर तक का बॉन्ड जमा करने के लिए कह सकते हैं. इस फैसले की घोषणा शुक्रवार को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित एक नोटिस के जरिए की गई. यह नियम 50 देशों के B-1 और B-2 वीजा आवेदकों पर लागू होगा, जिनमें से अधिकतर देश अफ्रीका में हैं. यह नया नियम 3 अगस्त से लागू हो जाएगा.

नोटिस के अनुसार, कॉन्सुलर अधिकारी वीजा जारी करने की शर्त के रूप में संबंधित गैर-प्रवासी वीजा आवेदकों से अपनी तरफ से तय की गई राशि का बॉन्ड जमा करने के लिए कह सकते हैं. यह राशि अधिकतम 20,000 डॉलर तक हो सकती है. वीजा बॉन्ड प्रोग्राम को पहली बार वर्ष 2025 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था. इसका मकसद यह जांचना था कि क्या आर्थिक बॉन्ड की व्यवस्था वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रुकने वाले लोगों की संख्या कम करने में मदद कर सकती है.

अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस पायलट प्रोग्राम से मिले नतीजे इतने पॉजिटिव रहे कि इसे स्थायी रूप से लागू करने का फैसला लिया गया. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस में कहा गया है कि 2025 के वीजा बॉन्ड पायलट प्रॉग्राम ने विदेश विभाग, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और ट्रेजरी विभाग को इस योजना की व्यवहारिकता का आकलन करने का मौका दिया और इससे यह साबित हुआ कि बॉन्ड प्रोग्राम वीजा नियमों का पालन सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तरीका है. भारत इस सूची में शामिल नहीं है. वर्तमान में भारत के नागरिकों को B-1 या B-2 वीजा के लिए आवेदन करते समय इस नए नियम के तहत कोई वीजा बॉन्ड जमा नहीं करना होगा.

अमेरिका के विदेश विभाग ने संकेत दिया है कि भविष्य में इस कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाया जा सकता है और इसमें अन्य देशों को भी शामिल किया जा सकता है. यह कार्यक्रम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से लागू किए गए बड़े इमिग्रेशन अभियान का हिस्सा माना जा रहा है. जब यह योजना पायलट आधार पर शुरू की गई थी, तब कॉन्सुलर अधिकारी आवेदकों से 5,000 डॉलर, 10,000 डॉलर या 15,000 डॉलर तक का बॉन्ड मांग सकते थे. अब स्थायी नियम में 5,000 डॉलर वाला विकल्प हटा दिया गया है और अधिकतम राशि बढ़ाकर 20,000 डॉलर कर दी गई है.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस नीति का मुख्य मकसद लोगों को अपने वीजा की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में अवैध रूप से रुकने से रोकना है. हालांकि, इमिग्रेशन समर्थकों का मानना है कि इससे वास्तविक कारोबारी यात्रियों और घूमने-फिरने के लिए आने वाले पर्यटकों पर भी असर पड़ सकता है और वे अमेरिका आने से हतोत्साहित हो सकते हैं. ट्रंप प्रशासन ने हाल के समय में इमिग्रेशन नियमों को और सख्त किया है. कुछ वीजा श्रेणियों के लिए फीस बढ़ाई गई है और वीजा आवेदकों तथा अमेरिका में पहले से रह रहे कुछ प्रवासियों की सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच भी बढ़ा दी गई है.

## इंडोनेशिया में जहाज में लगी आग, 5 की मौत

**नई दिल्ली।** इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास एक पैसेंजर जहाज में आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई. 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं. अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है. घटना के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इंडोनेशिया की रेस्क्यू एजेंसी के मुताबिक, आग लगने के समय जहाज में 271 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे. रविवार दोपहर तक कम से कम 225 लोगों को बचा लिया गया था. वहीं, लापता लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, यह जहाज पूर्वी जावा प्रांत के सुराबाया से दक्षिण सुलावेसी के मकासर जा रहा था. तभी जावा के उत्तर पूर्वी तट के पास मदुरा द्वीप के पास इसमें आग लग गई. रेस्क्यू के लिए कई जहाज तैनात किए गए हैं. वहीं, अधिकारी आसपास के पानी में तलाशी अभियान चला रहे थे. जहाज पर सवार लोगों को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे. फिलहाल आग की वजह का पता नहीं लगाया जा सका है. घटना इंडोनेशिया में साल भर पहले एक अन्य जहाज में लगी भयंकर आग के बाद सामने आई है. जुलाई 2025 में नॉर्थ सुलावेसी प्रांत के पास एक यात्री जहाज में आग लगी थी. इसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, लगभग 150 लोगों को बचाया गया था. उस जहाज का नाम KM बार्सिलोना 5 था. इसमें 280 लोग सवार थे।

## किश्तों में सैलरी दे रही SpiceJet

**नई दिल्ली।** नकदी संकट से जूझ रही घरेलू एयरलाइन SpiceJet इन दिनों एक बार फिर आर्थिक परेशानियों को लेकर सुर्खियों में है. हाल ही में एयरलाइन ने कबूल किया है कि मौजूदा हालात के कारण कर्मचारियों का वेतन एकमुश्त देने के बजाय किस्तों में जारी किया जा रहा है. साथ ही SpiceJet फिलहाल अपनी पूरी क्षमता से काफी कम उड़ानों का संचालन कर रही है. कंपनी ने बताया कि जूनियर और सपोर्ट कर्मचारियों को मई महीने का सैलरी पेमेंट कर दिया गया है, जबकि कुछ बाकी कर्मचारियों को सैलरी किस्तों में पेमेंट किया जा रहा है. हालांकि, बाकी कर्मचारियों का पेमेंट कब तक पूरा होगा इस बारे में कंपनी ने नहीं बताया है. SpiceJet वर्तमान में प्रतिदिन करीब 85 उड़ानों का संचालन कर रही है. ग्रीष्मकालीन शेड्यूल के तहत कंपनी ने उड़ाने करीब 140 उड़ानों की योजना बनाई थी. यानी एयरलाइन फिलहाल अपनी तय क्षमता से काफी कम उड़ानें उड़ रही है.

## Amazon दे रहा 80% तक डिस्काउंट

**नई दिल्ली।** अगर आप भी आने वाले दिनों में कोई नया गैजेट या अपने घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके बेहद काम की है. आने वाले दिनों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon India पर अपनी Freedom Sale लेकर आ रहा है. इस सेल में आपको मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस जैसी कई प्रोडक्ट्स की खरीदारी पर शानदार ऑफर्स और भारी छूट मिल सकती है. Amazon की इस सेल के दौरान ग्राहकों कई बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स को कम कीमत में खरीदने का मौका दिया जाएगा. खास बात यह है कि इस दौरान कुछ होम अप्लायंस पर आपको भारी छूट दी जा सकती है, जिसमें 80% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है. Amazon इंडिया ने अपनी अपकमिंग Freedom Sale के लिए एक खास पेज भी तैयार किया है, जिससे आपको सेल से जुड़ी जानकारी और ऑफर्स के बारे में अपडेट मिलता रहेगा.

## भारत के अभ्यास मैच के शेड्यूल में बदलाव

**नई दिल्ली।** भारतीय क्रिकेट टीम की एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज श्रीलंका के साथ है, जो 15 अगस्त से शुरू होगी. पहला टेस्ट गॉल में खेला जाएगा, जिससे पहले शुभमन गिल एंड टीम को एक वार्म-अप मैच भी खेलना है. लेकिन अब खबर आई है कि अभ्यास मैच के शेड्यूल में बदलाव हुआ है. बता दें कि श्रीलंका दौरे पर भारत को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका के लिहाज से महत्वपूर्ण है. गॉल टेस्ट से पहले भारत और श्रीलंका X I के बीच एक वार्म-अप मैच होगा. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार 4 दिन के होने वाले इस मैच को छोटा कर दिया गया है, अब ये 3 दिन का होगा. अभ्यास मैच 7 अगस्त से 9 अगस्त के बीच होगा।

# MI में ही रहेंगे हार्दिक पांड्या?

## ट्रेड डील की खबरों पर फ्रेंचाइजी ने तोड़ी चुप्पी

हार्दिक पांड्या से मुंबई इंडियंस को बहुत उम्मीदें थी, तभी तो फ्रेंचाइजी ने रोहित शर्मा को हटाकर ऑलराउंडर को कप्तान नियुक्त किया. रोहित की कप्तानी में MI ने 5 ट्रॉफी जीती, लेकिन फिर अचानक उन्हें हटाकर हार्दिक को कमान सौंप दी गई. उनकी कप्तानी में टीम अच्छा नहीं कर पाई, 3 में से 2 सीजन तो टीम प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई. रिपोर्ट सामने आई कि आगामी सीजन के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले हार्दिक ट्रेड के जरिए MI का साथ छोड़ सकते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वह CSK में जा सकते हैं और KKR, DC भी उन्हें लेना चाहती है. अब इस मामले में पहली बार MI की तरफ से कोई बयान सामने आया है.

स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट में मुंबई इंडियंस के प्रवक्ता ने कहा है कि खिलाड़ियों की ट्रेड को लेकर उनकी किसी भी फ्रेंचाइजी से कोई बात नहीं चल रही है. उन्होंने कहा है कि अभी पिछले सीजन के बाद का रिव्यू चल रहा है. जब हमारा रिव्यू पूरा हो जाएगा, तब ही ट्रेड संभव है. अभी किसी भी फैसले पर समय लगेगा, क्योंकि विकल्पों पर बात हो रही है.

हार्दिक पांड्या ने 2024 से मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली, इससे पहले उनकी कप्तानी में 2022 में गुजरात टाइटंस ने खिताब जीता. 2023 में भी GT फाइनल तक पहुंची, जिसके बाद वह वापस MI में लौट आए जहां से उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की. रोहित को हटाकर उन्हें कप्तान बनाया गया, जिसकी उस समय काफी आलोचना भी हुई थी.

मुंबई इंडियंस ने 2020 के बाद से कोई खिताब नहीं जीता है, इससे पहले रोहित की कप्तानी में टीम 5 बार की चैंपियन रह चुकी है. मुश्किल है कि अगर हार्दिक दूसरी टीम में जाते भी है तो रोहित को वापस कप्तानी सौंपी जाए. नए कप्तान के रूप में तिलक वर्मा का नाम सबसे आगे है.

## CWG के बीच भारतीय नक्शे को लेकर विवाद, बॉक्सर लवलीना ने जताई आपत्ति

**नई दिल्ली।** लवलीना बोरगोहेन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल जीतने के बाद तब नाराज हो गई, जब उन्होंने ग्लासगो में नेपकिन पर भारत का अधूरा नक्शा देखा. उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए माइक में सबके सामने कहा कि इससे उन्हें दुख पहुंचा. बता दें कि शनिवार को भारत के 7 बॉक्सर ने गोल्ड जीता, हालांकि लवलीना चूक गई. उन्होंने सिल्वर मेडल जीता.

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में शनिवार का दिन मुक्केबाजों के लिए शानदार रहा, 7 गोल्ड सिर्फ इसी खेल में आए. लवलीना बोरगोहेन ने सिल्वर मेडल जीता, जो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी से हार गईं. शानदार दिन के बाद भारतीय दल के सदस्य ग्लासगो में स्थिति एक भारतीय रेस्टोरेंट में गए. 'मिस्टर सिंह इंडिया' नाम के इस रेस्टोरेंट में जो नैपकिन रखे गए थे, उस पर भारत का आउटलाइन मैप बना हुआ था. इस पर लवलीना की नजर पड़ी, जिसमें उन्हें कुछ अजीब दिखा.लवलीना बोरगोहेन ने देखा कि इस नक्शे पर देश के नॉर्थ-ईस्ट हिस्से को पूरा नहीं दिखाया गया है. उन्होंने इसका विरोध किया। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह माइक में अपनी नाराजगी जाहिर करती हुई दिख रही हैं. लवलीना कह रही हैं, "प्लीज, आप बुरा मत मानिए. मुझे ये थोड़ा बुरा लगा कि इंडिया मैप में ये हमारा नार्थ ईस्ट नहीं है. बाहर भी ऐसा, हमारे नार्थ ईस्ट को कट कर दिया है।

# अभिषेक शर्मा ने वनडे में ठोकी डबल सेंचुरी, 91 गेंद में बनाए 233 रन

**नई दिल्ली।** अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. अब उन्होंने तबाही मचाते हुए वनडे मैच में दोहरा शतक लगा दिया है. यह कारनामा उन्होंने पंजाब स्टेट इंटर-डिस्ट्रिक्ट सीनियर वनडे टूर्नामेंट में किया है. अभिषेक ने केवल 91 गेंद में 233 रन जड़ दिए. इस ऐतिहासिक पारी में उन्होंने 25 छक्कों सहित 40 बाउंड्री लगाईं.

इस इंटर-डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा अमृतसर की टीम के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने तरन तारन टीम के खिलाफ 91 गेंद में 233 रन बनाए. 25 छक्के और 15 चौकों से सजी इस पारी में अभिषेक ने 256.04 के तूफानी स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इस मैच के स्कोरकार्ड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.अभिषेक शर्मा की डबल सेंचुरी की बदौलत अमृतसर की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 533 रन बना डाले. अभिषेक के अलावा उनके ओपनिंग जोड़ीदार अभय चौधरी ने 93 रन, जबकि अभिनव शर्मा ने भी 51 रनों की धुआंधार पारी खेली.

अभिषेक शर्मा के बल्ले में जैसे स्प्रिंग लगी थी. उन्होंने 233 रनों की पारी में 210 रन तो बाउंड्री से ही बना डाले. विपक्षी टीम तरन तारन के गेंदबाज चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे. अंततः आशीष लॉरेंस ने उन्हें अनिकेत सिंह के हाथों कैच करवाया।

# अचानक छत्तीसगढ़ छोड़ पुडुचेरी की टीम से जुड़े शशांक सिंह

**नई दिल्ली।** इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज शशांक सिंह ने अपनी घरेलू क्रिकेट टीम छत्तीसगढ़ का साथ छोड़ दिया है. शशांक साल 2019 से ही घरेलू क्रिकेट में छत्तीसगढ़ के लिए खेल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पोंडिचेरी को जॉइन कर लिया है. शशांक नए खुद बताया कि वे अगले सीजन से पोंडिचेरी के लिए खेलेंगे. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पोंडिचेरी के पूर्व अध्यक्ष पी दामोरन ने बताया कि वे बहुत जल्द तीसरे गेस्ट प्लेयर के नाम पर मुहर लगाएंगे. शशांक सिंह ने बताया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ टीम का साथ छोड़ दिया है, इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) से एनओसी भी प्राप्त कर ली है. वे 2026-27 घरेलू सीजन से पोंडिचेरी के लिए खेलेंगे. पंजाब किंग्स के इस स्टार बल्लेबाज नए CSCS पर आरोप लगाते हुए कहा कहा कि पिछले सीजन उन्हें गंभीर चोट आई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने उनका साथ नहीं दिया था. शशांक ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उनका टीम में चयन तक नहीं किया गया था।

## EPFO में 1816 करोड़ का घोटाला, रिलायंस कैपिटल के खिलाफ FIR

**नई दिल्ली।** केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, उसके पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी और कुछ अज्ञात लोक सेवकों और दूसरे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. मामला EPFO को कथित तौर पर 1,816.22 करोड़ का नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है. सीबीआई के मुताबिक, ये कार्रवाई श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले EPFO की शिकायत के आधार पर की गई है. एजेंसी अब पूरे निवेश और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगी. जांच एजेंसी के अनुसार, साल 2013 और 2014 के दौरान रिलायंस कैपिटल ने सिक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी किए थे. आरोप है कि EPFO के करीब 2,500 करोड़ इन डिबेंचरों में चार पोर्टफोलियो मैनेजरों के जरिए निवेश किए गए. बाद में इन निवेशों से EPFO को मूलधन और ब्याज मिलाकर 1,816.22 करोड़ का कथित नुकसान हुआ. इसमें करीब 1,007.55 करोड़ का मूल नुकसान और 808.67 करोड़ की ब्याज देनदारी शामिल बताई गई है।

# इस महीने से महंगी होंगी रोजमर्रा की वस्तुएं

**नई दिल्ली।** अगर आप अगस्त से त्योहारों की खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपकी जेब का बजट बिगाड़ सकती है. देश की कई बड़ी कंज्यूमर कंपनियां लगातार दूसरे 3 महीने में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें ज्यादा करने जा रही हैं. डिटर्जेंट, साबुन, बर्तन धोने की बार, नमक, पेंट, टायर और कई दूसरे रोजमर्रा के सामान महंगे होने वाले हैं. कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल और फ्यूल महंगा होने की वजह से दाम ज्यादा करना मजबूरी हो गया है.

देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा है कि आने वाले 3 महीने में डिटर्जेंट और बर्तन धोने की बार जैसी होम केयर कैटेगरी में एक एक कर के कीमतें ज्यादा की जाएंगी. इसके अलावा एशियन पेंट्स, डोडला डेयरी समेत कई दूसरी कंपनियों ने भी प्राइस हाइक का हिंट दिया है. कंपनियों का कहना है कि कच्चे तेल से बनने वाले कच्चे माल की कीमतें लगातार ज्यादा हो रही हैं, जिससे कॉस्ट पर दबाव ज्यादा हो गया है.

### मिडिल ईस्ट तनाव का असर

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईरान से जुड़े हालात का असर अब भारतीय बाजार पर भी दिखाई देने लगा है. कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा रहने से कंपनियों को प्रोडक्शन महंगा पड़ रहा है. इसी वजह से हैवेल्स इंडिया अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम 8% तक ज्यादा कर दी है, जबकि टाटा कंज्यूमर ने नमक की कीमत करीब 7% ज्यादा कर दी है. अगर यही हाल बनी रही तो आने वाले महीनों में और भी कंपनियां कीमतें ज्यादा कर सकती हैं.

अगस्त से नवंबर तक देश में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आते हैं. यही समय कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा बिक्री वाला सीजन होता है. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि मजबूत मांग के लिए कस्टमर ज्यादा हुई कीमतों के बावजूद खरीदारी करेंगे और इसका असर बिक्री पर ज्यादा नहीं पड़ेगा.

### घबराएं नहीं, अपनाएं जरूरी कदम

# UPI से दो बार कट गए पैसे? कैसे मिलेगा रिफंड

आज के समय में ज्यादातर लोग पेमेंट के लिए कैश के बजाय UPI का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. हालांकि कई बार डिजिटल गड़बड़ी या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से एक ही ट्रांजैक्शन से दो बार रकम कट जाती है. ऐसे में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अब उनका पैसा वापस कैसे मिलेगा. खासतौर पर उन्हें लगता है कि उनका पैसा अब फंस चुका है. अगर आप भी रोजमर्रा के पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं और आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आप कुछ जरूरी कदम उठाकर आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं. RBI के नियमों के मुताबिक, अगर आपके खाते से पैसे कट जाता है लेकिन लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचे, तो निर्धारित समय के अंदर रकम अपने आप वापस कर दी जाती है.

### सबसे पहले क्या करें?

- ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करें.
- दोनों पेमेंट की ट्रांजैक्शन आईडी और 12 अंकों का RRN नंबर नोट कर अपने पास सुरक्षित रखें.
- साथ ही यह देखें कि दोनों पेमेंट सफल हुआ है या किसी एक की स्थिति पेंडिंग या फेल है.
- स्क्रीनशॉट और पेमेंट से जुड़ी जानकारी संभालकर रखें.

### अगर व्यापारी को दो बार पेमेंट पहुंच जाएं

अगर आपका दोनों ट्रांजैक्शन सफल हो चुका है और व्यापारी के खाते में दो बार रकम पहुंच गया है, तो ऐसे में रिफंड की प्रोसेस अलग हो सकती है. ऐसे मामलों में पैसा ऑटोमैटिक वापस नहीं आता है, बल्कि आपको अपने UPI ऐप या बैंक के जरिए शिकायत दर्ज करनी होगी. साथ ही इसके लिए आपको व्यापारी, बैंक या पेमेंट सेवा प्रदाता के माध्यम से रिफंड प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है.

### कहां करें शिकायत?

- सबसे पहले उसी UPI ऐप में शिकायत दर्ज करें, जिससे पेमेंट किया गया था.
- जरूरत पड़ने पर अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें.
- शिकायत करते समय ट्रांजैक्शन आईडी, RRN नंबर, तारीख, राशि और व्यापारी की जानकारी साथ रखें.
- जरूरत पड़ने पर बैंक विवाद (Dispute) प्रक्रिया शुरू कर सकता है.

### रिफंड आने में कितना समय लग सकता है?

फेल या पेंडिंग ट्रांजैक्शन में रकम तय समय के अंदर अपने आप वापस आ सकती है.अगर पेमेंट दो बार सफल हो चुका है, तो रिफंड में कुछ एक्स्ट्रा समय लग सकता है क्योंकि इसकी जांच अलग प्रक्रिया के तहत की जाती है.

### रिफंड के नाम पर ठगी से कैसे बचें?

- अपना UPI PIN, OTP या बैंकिंग जानकारी किसी के साथ शेयर न करें.
- रिफंड पाने के लिए कभी भी UPI PIN दर्ज करने की जरूरत नहीं होती.
- किसी अनजान शख्स के कहने पर QR कोड स्कैन न करें.

## 6 साल बाद भारत-चीन व्यापार शुरू

**नई दिल्ली।** भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार करीब छह साल बाद फिर शुरू हो गया है. कोविड-19 महामारी के दौरान बंद हुए इस पारंपरिक व्यापार मार्ग को अब दोबारा खोला गया है. लिपुलेख पास (उत्तराखंड), शिपकी ला (हिमाचल प्रदेश) और नाथू ला (सिक्किम) जैसे प्रमुख रास्तों से व्यापार गतिविधियां दोबारा शुरू होने जा रही हैं. इस फैसले से सीमावर्ती इलाकों के व्यापारियों, स्थानीय कारोबार और छोटे उद्योगों को फायदा मिलने की उम्मीद है. लंबे समय से बंद पड़े इस व्यापार से दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

### भारत से चीन को क्या-क्या भेजा जाएगा?

ऊन और ऊनी उत्पाद, पश्मीना उत्पाद, कालीन और हस्तशिल्प सामान, कृषि उत्पाद, जड़ी-बूटियां और हर्बल उत्पाद, स्थानीय स्तर पर तैयार वस्तुएं, लंदन जाने वाली डायरेक्ट उड़ानें बंद, देश की इस बड़ी विमान कंपनी ने लिया फैसला

### चीन से कौन-कौन सी चीजें आ सकती हैं?

ऊनी कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रोजमर्रा के उपयोग की चीजें, मशीनरी और छोटे उपकरण, कुछ कृषि और घरेलू उपयोग की चीजें।

# सुशासन की खेती में जहरीले थायरम पाउडर का छिड़काव

## छत्तीसगढ़ में थायरम पाउडर की खरीदी में भारी अनियमितता

- पथर्रा-धरमपुरा में ही 200 बोरी थायरम पाउडर की हेरा-फेरी
- वर्ष 2022-23 में मुंगेली-बेमेतरा बीज प्रबंधक ने किया खेल
- बीज प्रबंधक आकाश सोलंकी पर गड़बड़ियों का गंभीर आरोप
- जांच कमेटी की रिपोर्ट में दोषी बताने के बाद भी कार्रवाई नहीं
- कृषि मंत्री नेताम और सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी बेखबर

**प्रदीप चंद्रवंशी (मुख्य संवाददाता)।** यह कहानी सिर्फ फंगीसाइड कैमिकल यानी थायरम पाउडर की नहीं है, बल्कि इस खतरनाक फंगीसाइड पाउडर की खरीदी में किये गए सनसनीखेज घोटाले की भी है। खासकर छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विभाग के अधीनस्थ बीज निगम द्वारा हजारों बोरी थायरम पाउडर की अफरातफरी करने की है। अकेले बेमेतरा और मुंगेली जिले में ही तक़रीबन 200 बोरी थायरम पाउडर खरीदी कागजों में कर ली गई। इस हेराफेरी में बीज निगम के अंतर्गत बीज प्रबंधकों ने लाखों रूपये कमाया भी। सुशासन की छाती में मुंग डालने वाले ऐसे आरोपी बीज प्रबंधकों को कृषि विभाग के आला अफसरों और बीज निगम के जिम्मेदारों का पूरा प्रश्रय मिला हुआ है। थायरम पाउडर ऐसे प्रशासकीय फैसलों से जुड़ा हुआ है जो सीधे राज्य की खाद्य सुरक्षा, किसानों की जिंदगी और आम लोगों की सेहत से सरोकार रखते है।

शहर सत्ता/रायपुर। खेती और किसानी के नाम पर छत्तीसगढ़ में घोटालेबाज अधिकारी जमकर भ्रष्टाचार की फसल ऊगा रहे हैं। मजे की बात यह है कि खतरनाक जहरीले फंगीसाइड कैमिकल यानी थायरम पाउडर की खरीद-फरोख्त में भी अफसरों के लालच ने सारी हदें पार कर दी हैं। मामला छत्तीसगढ़ के धरमपुरा जिला मुंगेली और पथर्रा जिला बेमेतरा के बीज केंद्र का है। कांग्रेस शासन कल की रवानगी और सुशासन की आमद यानि कि वर्ष 2022-23 का है।

जानकारी के मुताबिक फर्जी चालान(चालान नंबर 138318DT 23 /09/2021 को वाहन क्रमांक सीजी-9286 में 200 बोरी थायरम पाउडर लोड कर प्रक्रिया केंद्र पथर्रा बेमेतरा भेजा जाना बताया गया। लेकिन प्रक्रिया केंद्र पथर्रा से प्राप्त चालान, सील, हस्ताक्षर और रिसीविंग लेटर को मूल चालान बुक में चस्पा कर दिया गया। लेकिन जोगी राम द्वारा सील-हस्ताक्षर फर्जी पाए जाने की बुनियाद पर निरस्त कर दिया गया था। लेकिन जब मामले की पड़ताल के लिए बीज प्रबंधक पथर्रा में RTI तब इस पुरे घोटाले और इसे अंजाम देने वाले बीज प्रबंधक आकाश सोलंकी का नाम उजागर हो गया। आकाश के खिलाफ जांच समिति गठित की गई थी उनकी जांच में भी आकाश सोलंकी को स्पष्टतः 200 बोरी थायरम घोटाले का किंगपिन मन गया। परंतु जांच समिति की रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करने के बाद भी आज तलक आकाश सोलंकी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तो दूर मुख्यालय रायपुर में पदस्थ कर दिया गया। जबकि जांच समिति की रिपोर्ट में आकाश सोलंकी को दोषी और अधिकारीयों के करीबी होने का लाभ मिलना बताया गया है।

### बीज निगम में घोटालेबाजों का सिंडिकेट

किसी सिंडिकेट की तरह संचालित कृषि विभाग के अधीनस्थ छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड में ऐसे घोटालेबाज अफसर, बीज प्रबंधक और स्टाफ बेख़ौफ़ कार्यरत हैं। घोटालेबाजी का अंदाज़ इसी से लगाया जा सकता है कि 3 साल पहले के 200 बोरी थायरम पाउडर खरीद की गड़बड़ी करने वाले अब एमडी और अध्यक्ष के करीबी हैं।

### सजा के बदले मिला अफसरों का दुलार

जांच समिति अध्यक्ष डीडीए एल आर जुर्री, बीज प्रबंधक जोरा पायल अग्रवाल, बीज प्रबंधक धरमपुरा प्यार सोनकर, संदीप सोनकर बीज प्रबंधक पथर्रा जिला बेमेतरा जांच समिति में थे। इन्हों ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा है आरोपी आकाश सोलंकी को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछतछ किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में तीन बार बयान और दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया था। पत्र क्रमांक 2023-24 /392/दिनांक 17,01.2024 को लिखित बयान दस्तावेज पक्ष में प्रस्तुत करने कहा गया था। लेकिन आरोपी आकाश सोलंकी ने आज तक किसी भी प्रकार के साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। फ़िलहाल आकाश एमडी का पीए बना दिया गया।

### 40 हजार क्विंटल थायरम पाउडर घोटाला

जानकारी के मुताबिक थिराम पाउडर की कीमत प्रति क्विंटल 16,525 रु.है। ऐसे में महज एक ही बीज केंद्र से अगर तकरीबन 200 बोरी की गड़बड़ी मिलती है तो अंदाज लगाया जा सकता है कि प्रदेश के समस्त बीज केंद्रों में ये आंकड़े तक़रीबन 40 हजार क्विंटल को पार करते हैं। प्रति बोरी कीमत 16 हजार 500 रूपये है तो 40 हजार क्विंटल का तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रु होता है।

### जांच कमिटी ने माना आरोपी को सरंक्षण प्राप्त

आरोपी द्वारा आरोपों का लिखित बयान दर्ज नहीं करवाने का मुख्या कारण मुख्यालय में पदस्थी के साथ मुख्यालय के एमडी का पीए होने की बात सामने आई। तथा मुख्यालय बीज निगम रायपुर के एमडी का पीए बनकर प्रभाव का दुरूपयोग करना है। उच्चाधिकारियों के साथ और शाह पर काम करना एवं आरोपी को वरिष्ठ अधिकारीयों से संरक्षण का भी उल्लेख जाँच समिति ने किया। निर्देशों का पालन नहीं किये इसलिए स्पष्टतः वो दोषी हैं। जाँच समिति के सदस्यों संदीप सोनकर, पायल अग्रवाल ने जाँच प्रतिवेदन में हस्ताक्षर करने जब आरोपी को बोले तो उल्टा आरोपी ने समिति को भ्रष्ट और 50 हजार रूपये मांगने का आरोप लगाया।

### मई ने जांच प्रतिवेदन में कार्रवाई के लिए लिखा था

जांच समिति अध्यक्ष एलआर जुर्री का कहना है उन्हों ने सख्त कार्रवाई की अनुशंसा बीज निगम अध्यक्ष, कृषि विकास निगम लिमिटेड मुख्यालय और कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय तथा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम , मुख्या सचिव विकासशील, पुलिस अधीक्षक रायपुर , मुंगेली कलेक्टर, थाना तेलीबांधा को जाँच समिति ने कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भी भेज दिया है। फिर भी विभागीय ख़ामोशी यह बताती है कि कृषि विभाग और इसके अधीनस्थ बीज निगम और मंडी बोर्ड में सिंडिकेट हावी है।

### निगम में श्रमिक सम्मान निधि भी देना बंद

भूपेश सरकार के वक्त श्रमिक सम्मान निधि मिल रही थी। साय सरकार में भी यह मिलती रही। लेकिन बीज निगम में अजय अग्रवाल के एमडी बनते ही सम्मान निधि देना अगस्त से बंद कर दिया गया है। बता दें की तकरीबन 4500 रूपये श्रमिक सम्मान राशि मिलने से छोटे कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी के लिए बहुत बड़ा सहारा होता था। लेकिन अचानक ही में यह राशि नहीं दी जा रही है।

### मंत्री क्या कहते हैं

*"कृषि मंत्री रामविचार नेताम का कहना है किउनकी जानकर में ऐसा कोई मामला अब तक नहीं आया है। फिर भी आप कह रहे हैं तो सम्बन्धित अधिकारीयों और बीज निगम से जानकारी मंगवाई जाएगी। कार्रवाई भी होगी।*

### सचिव बोले होगी कार्रवाई

*"सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने भी मामले जानकारी से इंकार किया है। आपने जो बताया है मैं उस पुरे मामले की पर्सनली जानकारी मंगवाकर जाँच करवाऊंगा। अगर ऐसा अनियमितता भरा मामला सामने आया है तो दोषी बक्शे नहीं जायेंगे।"*

# महिलाओं की सामूहिक ताकत से महका एमसीबी का जीराफूल धान

- 100 प्रतिशत अंकुरण से 10 एकड़ तक पहुंची सफलता की कहानी
- महिला एफपीओ ने 'हसदेव ब्रांड' को दी नई पहचान

**रायपुर।** आत्मनिर्भर भारत के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले की महिलाओं ने एक नई मिसाल कायम की है। सिद्धबाबा महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने सामूहिक प्रयास, वैज्ञानिक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों के दम पर सुगंधित जीराफूल धान की ऐसी सफलता की कहानी लिखी है, जो अब पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन रही है। महिलाओं की इस पहल ने न केवल खेती को लाभकारी बनाया है, बल्कि स्थानीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ाया है। महिला शेयरधारकों को संगठित कर गठित इस एफपीओ ने जीराफूल धान की खेती की शुरुआत उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और वैज्ञानिक पद्धति से तैयार नर्सरी के साथ की। कृषि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में किए गए बीज उपचार और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग का परिणाम यह रहा कि 100 प्रतिशत अंकुरण प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि ने महिला किसानों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया। सफल अंकुरण के बाद महिलाओं ने सामूहिक रूप से 10 एकड़ क्षेत्र में जीराफूल धान की खेती का विस्तार किया। समय पर रोपाई, संतुलित पोषण प्रबंधन, नियमित सिंचाई और सतत निगरानी के कारण खेतों में फसल शानदार स्थिति में है। आज लहलहाते धान के खेत महिला किसानों की मेहनत, अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व की जीवंत मिसाल बन चुके हैं।

इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि महिलाएं केवल खेतों में श्रम तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि बीज चयन, नर्सरी प्रबंधन, रोपाई, फसल संरक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादन प्रबंधन जैसी पूरी कृषि प्रक्रिया में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। इससे खेती के प्रति उनका दृष्टिकोण बदला है और कृषि उनके लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। एफपीओ का अगला लक्ष्य 'हसदेव ब्रांड' के तहत उच्च गुणवत्ता वाले सुगंधित जीराफूल चावल को प्रदेश और देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाना है। इसके लिए गुणवत्ता, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बेहतर विपणन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

# भूमिहीन मजदूर परिवारों के लिए संबल बनी शासन की योजनाएं



**रायपुर।** मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर और भूमिहीन परिवारों के जीवन में नई उम्मीद जगा रही हैं। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड निवासी श्री राम सिंह का परिवार इसका सजीव उदाहरण है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना और महतारी वंदन योजना से मिल रही नियमित आर्थिक सहायता ने उनके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया है।

राम सिंह ने बताया कि वे मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। स्वयं की कृषि भूमि नहीं होने के कारण पहले परिवार का खर्च चलाना कठिन था। राज्य शासन की दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत उन्हें प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। यह राशि परिवार की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और विपरीत परिस्थितियों में सहारा देने का काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि मिलती है। इस नियमित आर्थिक सहयोग से घरेलू खर्च, दैनिक आवश्यकताओं और अन्य जरूरतों को पूरा करने में सुविधा मिल रही है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक सुदृढ़ हुई है। राम सिंह ने बताया कि उनके परिवार में चार बच्चे हैं, जो समय-समय पर मजदूरी कर परिवार का सहयोग करते हैं। शासन की योजनाओं से मिलने वाली सहायता ने परिवार के जीवन-यापन को आसान बनाया है और जरूरत के समय आर्थिक सुरक्षा का आधार भी दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की हितग्राहीमूलक योजनाएं भूमिहीन और श्रमिक परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। श्री राम सिंह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की संवेदनशील पहल से उनके जैसे हजारों परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर और भविष्य के प्रति नया विश्वास मिला है।

# कलेक्टर साहब; ये क्या हो रहा है...?

## प्रदेश के अधिकांश तहसील कार्यालयों में भूमाफिया चला रहे गिरोह

- फॉरेंसिक लैब टेस्ट में फर्जी हस्ताक्षर और मृत्यु प्रमाणपत्र की तस्दीक
- रजिस्ट्री जमीन को तहसीलदार और पटवारी ने मानने से किया इंकार
- कूट रचना और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले के नाम जमीन नामांतरण
- पीड़ित दंपत्ति अब इंसाफ़ के लिए दिवानी न्यायालय की शरण में है
- अब अपनी ही जमीन के लिए लंबी विधिक प्रक्रिया और वाद व्यय झेल रहे

विशेष संवाददाता/शेख आबिद
मोबाईल नंबर 8109802829

कोई अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए पाई पाई पैसे जोड़कर एक जमीन का टुकड़ा खरीदे और उस पर अचानक चंद सालों बाद गिद्ध दृष्टि रखने वाले भूमाफिया फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रथम रजिस्ट्री जमीन को अपना बताने लगे तब कैसा लगेगा? मान लीजिए तिनका तिनका जोड़कर बुढ़ापे के लिए अपना एक आशियाना बनाने का ख्वाब संजोने वाले परिवार पर तब क्या बीतेगी जब कोई अनचाहा शख्स उनकी जमीन को अपना बताने लगे? यह सवाल किसी संवेदनशील व्यक्ति या आमजनों से पूछकर तो देखिए। तुर्रा यह कि लाखों रूपये खर्च कर पहली रजिस्ट्री करने वाले की फरियाद सुने बिना अगर पटवारी और तहसीलदार महज बेनामी वसीयत के कागजात के आधार पर जमीन का नामांतरण धंधेबाज के नाम कर दे तो आप टूट जायेंगे। मानसिक और आर्थिक तौर पर टूट चुका पीड़ित या तो लंबी विधिक प्रक्रिया में उलझकर रह जाएगा। नहीं तो कोई घातक कदम उठाने मजबूर हो जाएगा। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ की अधिकांश तहसीलों में कमोबेश ऐसे किस्सों की भरमार है। खासकर राजधानी रायपुर और आसपास के तहसील दफ्तर में ऐसे मामले आम हैं। पीड़ितों की आवाज तहसीलों में ही दबकर रह जाती है। वो खुशकिस्मत है जिन्हें कमिश्नर या कलेक्टर सहाब गंभीरता से लेते हैं तब उन्हें न्याय मिलता है और महकमे को बदनाम करने वाले पटवारी तहसीलदार को लताड़। हालांकि जरूरत है ऐसे जिम्मेदार अफसर और भू माफिया गैंग को सख्त समझाइश देने वाले कलेक्टर की।

## ऐसे पैदा हो गया जमीन का एक नया दावेदार

**शहर सत्ता/रायपुर।** मामला ग्राम नीलजा तहसील सारागांव के पास का है। दो महिलाओं श्रीमती संगीता तिवारी और श्रीमती पूर्णिमा सिंह के नाम खरीदी गई ढाई-ढाई एकड़ जमीन पटवारी, तहसीलदार की अनदेखी से विवाद में फंस गई है। दोनों ही महिलाओं के पतियों ने अपनी पत्नियों के नाम पर उक्त भूखंड ग्रीन्डले फारेस्ट इण्डिया लिमिटेड कंपनी की थी। कंपनी के दो डायरेक्टर स्वर्ण सिंह तथा संतोष कुमार सिकदर हैं। राजस्व अभिलेख में भी विधिसम्मत वर्णित भूमि खसरा नंबर 420 रकबा 1.222 हेक्टेयर है। खसरा नंबर 424 रकबा 0.356 हेक्टेयर कुल रकबा 1.784 हेक्टेयर है। कंपनी ने यह जमीन कृषकों से अपनी कंपनी के नाम क्रय किया था।

ग्रीन्डले फारेस्ट इण्डिया लिमिटेड के डायरेक्टर संतोष सिकदर और स्वर्ण सिंह द्वारा 9 सितंबर 2015 को बोर्ड ऑफ रेजुलेशन पास करके कंपनी की सुमित कुमार ठाकुर पिता अशोक कुमार निवासी 09 गुरुनानक, रेवेन्यू आनंद पेट्रोल पंप के सामने अमृतसर(पंजाब)को अधिकृत करते हुए खसरा नंबर 420, 424 और 427 कुल रकबा 1.784 हेक्टेयर को विक्रय करने अधिकृत किया था। बोर्ड ऑफ रेजुलेशन के आधार पर ही श्रीमती संगीता तिवारी पति महेंद्र कुमार तिवारी और श्रीमती पूर्णिमा सिंह पति एमपी सिंह निवासी अवधपुरी कॉलोनी भाठागांव रायपुर ने पंजीकृत विक्रय विलख दिनांक 15/09/2015 के माध्यम से क्रय किया है।

जमीं रजिस्ट्री करने के 4 से 5 दिन बाद महेंद्र कुमार तिवारी जब उक्त भूखंड को देखने गए तो स्थानीय निवासी ने बताया आपलोगों की जमीन को खुद की मालकियत बताने की सुचना दी। जानकारी से हड़बड़ाए दोनों रजिस्ट्रीकर्ता ऑनलाइन देखे तो पता चला कि राजेश कुमार दास पिता गोविन्द चंद दास निवासी चुना भट्टी रायपुर फर्जी वसीयतनामा दिनांक 15/05/2011 जो अपंजीकृत है और मात्र नोटराइज दस्तावेज और संतोष कुमार सिकदर पिता स्वर्गीय धरमदास के वसीयतनामा के आधार पर उक्त भूखंड को खुद मालिक बताया गया था। इतना ही नहीं सिर्फ वसीयतनामा के आधार पर खातेदार संतोष सिकदर की मौत 15/04/2013 को होना बताया गया।

कूट रचना कर जमीन के असली मालिक से रजिस्ट्री करने का दावा दस्तावेज प्रस्तुत कर पटवारी और तहसीलदार को पति-पत्नी की रजिस्ट्री को रद्द करने और जमीन का असली मालिक खुद को बताने दो दस्तावेज प्रस्तुत किए। मानो पटवारी और तहसीलदार भी कथित व्यक्ति को सही मानने तत्पर बैठे थे उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर वाले कागजात और मृत्यु प्रमाणपत्र को सहीं मान लिया। इस अप्रत्याशित दावेदार और तहसीलदार तथा पटवारी के व्यवहार से हतप्रभ दोनों महिला खरीदार और दोनों के पतियों ने तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री दस्तावेज और डे राशि समेत कई साक्ष्य दिखाए पर अतिरिक्त तहसीलदार धरसींवा(अब सारागांव)और पटवारी ने आनन फानन में कंपनी रेजुलेशन एक्ट की अनदेखी करते हुए राजेश कुमार दास के नाम भूखंड नामांतरण कर दिया।

### पुलिस से लेकर जिला प्रशासन तक नहीं हुई सुनवाई

दोनों ही महिला खरीदार के पतियों द्वारा कमिश्नर कार्यालय, पुलिस अधिकारियों और ADM तक गुहार लगाई हस्ताक्षर तथा असली मालिक के जिनसे उन्होंने जमीन खरीदा था उनका मृत्यु प्रमाणपत्र झूठा होने का दावा किया पर सब जगह उन्हें निराशा हाथ लगी। बता दें कि ग्रीन्डले कंपनी है और ऐसे में कंपनी की भूमि कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा संयुक्त रूप से अथवा बोर्ड ऑफ़ रेजुलेशन पास कर व्ययन या अंतरण किया जा सकता है। नियमतयः कंपनी की जमीन किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती। ऐसे में संतोष सिकदर को इसे किसी को वसीयत नहीं किया जा सकता।

### सरकारी लैब से जांच के बाद हुआ झूठ का खुलासा

पुलिस फॉरेंसिक लैब से अधिकृत अधिकारी विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षर का फर्जी होना बताया गया है। और मृत्यु प्रमाणपत्र भी झूठा साबित हो गया है। क्योंकि राजेश दास के मुताबिक संतोष सिकदर की मृत्यु 15/04/2013 को होना बताया गया था। जबकि कंपनी रेजुलेशन (विक्रय करने हेतु संकल्प पत्र)में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जारी रेजुलेशन में संतोष कुमार सिकदर ने संगीता तिवारी और पूर्णिमा सिंह को भूमि क्रय के लिए दिनांक 17/02/02015 ने हस्ताक्षरित और निष्पादित किया है। बोर्ड ऑफ़ रेजुलेशन भी 09/09/2015 में भी निष्पादन किया गया है।

### सुलगते सवाल

- संतोष सिकदर की मृत्यु प्रमाण पत्र पखांजूर छत्तीसगढ़ से कैसे बन गया ?
- पखांजूर छत्तीसगढ़ के मृत्यु प्रमाण पत्र में 15 अप्रैल 2013 बताई गई है
- जबकि पश्चिम बंगाल के ग्राम पंचायत मोहनपुर के मृत्यु प्रमाण पत्र में 09/10/2025 है
- क्यों तहसीलदार, पटवारी और एसडीएम सिर्फ वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये ?
- फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, फर्जी हस्ताक्षर बनाने और फर्जी गवाह पर कार्रवाई होगी ?

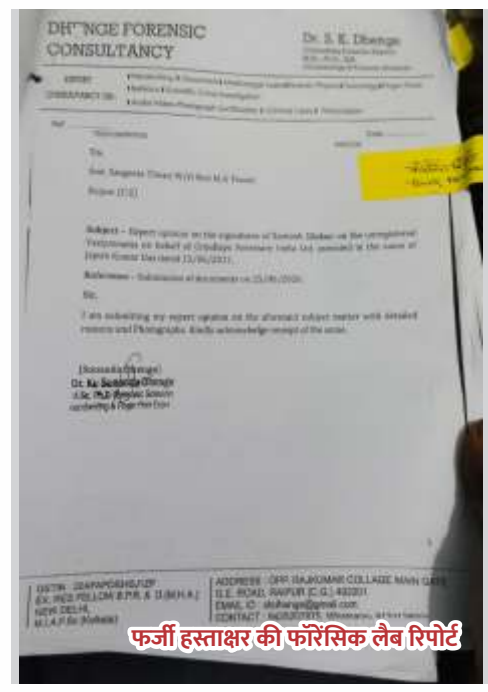

फर्जी हस्ताक्षर की फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट

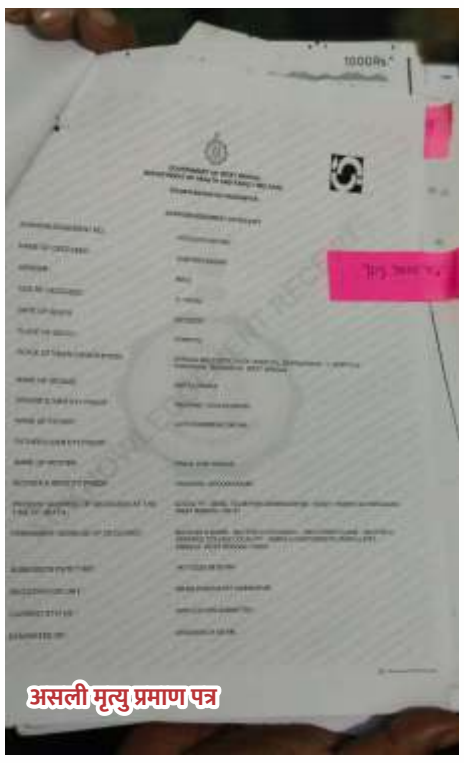
असली मृत्यु प्रमाण पत्र

नकली मृत्यु प्रमाण पत्र

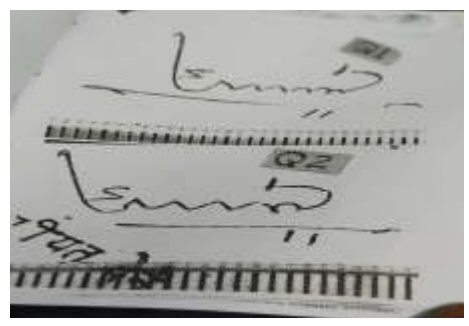

गवाह

पीड़ीत महिला खरीददार

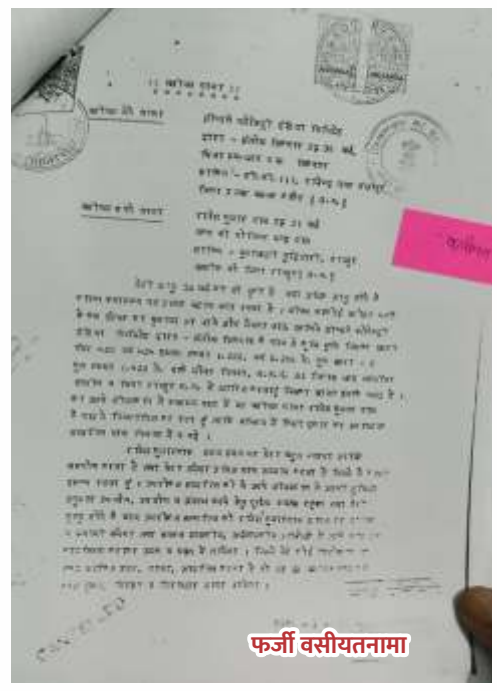
फर्जी वसीयतनामा

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27